



एक नज़र

नेपाल-भारत सीमा पर तनाव, हिंसा के बाद बॉर्डर सील

नई दिल्ली। पड़ोसी देश नेपाल एक बार फिर हिंसा की चपेट में आ गया है। भारतीय सीमा से सटे नेपाल के पारसा और धनुषा धाम जिले में हिंसा भड़क उठी है। पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच भारत-नेपाल सीमा भी सील कर दी गई है।

धनुषा जिले में मस्जिद गिराने के बाद नेपाल में सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी सामने आई हैं।

पारसा के बीरगंज में हिंसक प्रदर्शन पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। पारसा जिले की सीमा बिहार के रक्सौल जिले से लगती है। दक्षिणी नेपाल में सीमा से आवाजाही रोकने के लिए भारतीय सीमा भी सील कर दी गई है।

आदर्श नगर बिल्डिंग में लगी भीषण आग

नई दिल्ली। दमकल कर्मियों के मुताबिक, मंगलवार देर रात 2.39 बजे पांचवीं मंजिल पर स्थित फ्लैट में आग लगने की सूचना मिली थी। आग पर काबू पाने के बाद दमकल कर्मियों ने तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान कमरे से तीन जले हुए शव मिले।

आदर्श नगर स्थित दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) क्वार्टर में सोमवार देर रात लगी आग में एक परिवार के तीन सदस्यों की जलकर मौत हो गई। मृतकों की पहचान 42 साल के अजय विमल, उनकी पत्नी नीलम और 10 साल की बेटी जाह्नवी के रूप में हुई है।

पश्चिमी दिल्ली में मुसीबत बन रहे ई-रिक्षा

नई दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली में बेतरतीब खड़े ई-रिक्षा से लोग परेशान हैं। उत्तम नगर, द्वारका, नवादा, जनकपुरी और राजौरी गार्डन जैसे इलाकों में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी से रोजाना जाम लग रहा है। दफ्तर, स्कूल और अस्पताल जाने वाले लोग घंटों सड़कों पर जूझने को मजबूर हैं। जबकि प्रशासनिक कार्रवाई कागजों तक ही सीमित नजर आ रही है।

'अब जेल ही मेरी जिंदगी है, दूसरों की रिहाई से खुश हूँ', जमानत नहीं मिलने पर बोले उमर खालिद

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। वहीं इसी केस में पांच अन्य आरोपियों को जमानत दी गई है।

2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दोनों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत



प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

हालांकि इसी मामले में कोर्ट ने पांच अन्य आरोपियों को जमानत दे दी है। जमानत पाने वालों में गुलाफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद शामिल हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद मामले से जुड़े लोगों और समर्थकों के बीच

अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उमर खालिद ने अपनी साथी बानो ज्योत्सना लाहिरी से बातचीत में कहा कि अब जेल ही उनकी जिंदगी बन गई है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि अन्य को जमानत मिल गई है, भले ही उन्हें

खुद राहत नहीं मिली।

बानो ज्योत्सना लाहिरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बातचीत को साझा किया। उन्होंने लिखा कि उमर ने कहा कि वह दूसरों की जमानत से बहुत खुश और राहत महसूस कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह अगले दिन मुलाकात के लिए आएंगी, जिस पर उमर ने जवाब दिया कि अब यही जिंदगी है।

फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को आरोपी बनाया था। शरजील इमाम को 28 जनवरी 2020 को

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दिए गए भाषणों के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अगस्त 2020 में उन्हें इस बड़े साजिश मामले में भी गिरफ्तार किया गया। उमर खालिद को 11 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था।

सभी सातों आरोपियों पर यूएपीए और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस का आरोप है कि ये सभी दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड थे। यूएपीए की धारा 16 के तहत यदि किसी आतंकी कृत्य में किसी की मौत होती है तो दोषी को मौत या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है।

पुरानी दिल्ली:

फैज़-ए-इलाही मस्जिद पर होगा बुलडोज़र एक्शन? इलाके में तनाव, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा

नई दिल्ली। पुरानी दिल्ली में रामलीला मैदान के पास फैज़-ए-इलाही मस्जिद और उससे सटे कब्रिस्तान पर 7343 वर्ग फुट सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के आरोप को लेकर बुलडोज़र कार्रवाई की संभावना है। नगर निगम और भूमि एवं विकास कार्यालय ने इलाके का सर्वे किया है। कार्रवाई की खबर के बाद स्थानीय लोगों के विरोध को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है।

पुरानी दिल्ली में रामलीला

मैदान के पास स्थित फैज़-ए-इलाही मस्जिद पर बुलडोज़र कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। नगर निगम और भूमि एवं विकास कार्यालय की ओर से शनिवार को इलाके का संयुक्त सर्वे किया गया था। आरोप है कि मस्जिद और उससे सटे कब्रिस्तान ने करीब 7343 वर्ग फुट सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है।

प्रस्तावित कार्रवाई की खबर फैलते ही स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौके पर जुट गए और

विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालात को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस ने शनिवार और रविवार को क्षेत्र में गश्त कर हालात का जायजा लिया और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया।

बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई 'सेव इंडिया फाउंडेशन' नामक ट्रस्ट की ओर से दायर याचिका के आधार पर की जा रही है। इस ट्रस्ट



का नेतृत्व सोशल एक्टिविस्ट प्रीत सिरौही कर रहे हैं। वहीं मस्जिद प्रबंधन ने इस कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट

का रुख किया है। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

दिल्ली प्रदूषण पर आप का प्रदर्शन

विधानसभा में हंगामा... रेखा गुप्ता सरकार पर डेटा चोरी के आरोप

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन AAP ने आतिशी के नेतृत्व में प्रदूषण और डेटा चोरी के आरोपों पर प्रदर्शन किया। सदन में हंगामा भी हुआ। एलजी के भाषण के दौरान एक विधायक बाहर किए गए, जिसके बाद AAP विधायकों ने वॉकआउट किया।

दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन

सत्र के पहले दिन यानी आज नेता विपक्ष आतिशी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान AAP नेताओं ने रेखा गुप्ता सरकार पर डेटा चोरी का भी आरोप लगाया।

इसके अलावा, आम आदमी पार्टी के विधायकों द्वारा दिल्ली विधानसभा के सदन में भी हंगामा किया गया।

उपराज्यपाल की स्पीच के दौरान AAP विधायक संजीव कुलदीप कुमार को सदन से बाहर किया गया।

आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों ने विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट किया। पूर्व मुख्यमंत्री और AAP लीडर आतिशी ने लिखा, 'दिल्ली गैस चैंबर बन चुकी है। बच्चे और बुजुर्ग बीमार पड़ रहे हैं लेकिन बीजेपी की चार-इंजन

सरकार समाधान देने के बजाय AAP के आंकड़े मैनिपुलेट करने में लगी है।'

उन्होंने आगे कहा कि विधानसभा सत्र के पहले दिन इस आंख-कान मूंदे बैठी सरकार को जगाने के लिए हमने प्रदर्शन किया। दिल्लीवासियों के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं होगा। प्रदूषण पर जुमलेबाजी नहीं, ठोस और तुरंत कार्रवाई चाहिए।

जोहरान ममदानी के लेटर की क्या है मंशा?



Ali Aadil Khan
Editor

किस मुँह से करें उन के तगाफुल की शिकायत !!

खुद हम को मोहब्बत का सबक याद नहीं है !!

भारतीय मूल के 34 वर्षीय जोहरान ममदानी New York City Hall में न्यूयॉर्क शहर के 112वें मेयर के रूप में शपथ ले रहे थे और इधर दिल्ली में जोहरान ममदानी का उमर ख़ालिद के नाम लिखे लेटर की चर्चा शुरू हो गई थी।

कहा जा रहा है कि वो सिर्फ एक व्यक्तिगत सहानुभूति नहीं, बल्कि भारत की न्यायिक प्रक्रिया और आंतरिक संप्रभुता पर सीधा सवाल खड़ा करने जैसा है। लेकिन सवाल यह के किसी विदेशी जनप्रतिनिधि को यह मौका क्यों मिलता है और कौन देता है कि वह भारत के भीतर चल रहे संवेदनशील मामलों पर नैतिक उपदेश दे ?

बीजेपी का यह कहना कि 'भारत के अंदरूनी मामलों में दखल बर्दाश्त नहीं' यह महज़ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान और संवैधानिक चेतावनी भी हो सकती है। मगर अमेरिका पर इसका क्या असर होगा? शायद कुछ भी नहीं !!! और वैसे भी इंसानों सुनिश्चित करने की बात करना, सुझाना और याद दिलाना ये सब देश के स्वाभिमान को बढ़ाता है घटाता नहीं है। अलबत्ता अमेरिका जब भारतीय नागरिकों को बेड़ियों में जकड़कर भारत वापस भेज रहा था और दुनिया इस नज़ारे को देख रही थी तब ज़रूर देश का स्वाभिमान धूमिल हो रहा था। अफसोस के इसपर कोई टिपणी सरकार में बैठी पार्टी के नेताओं की तरफ से नहीं आई थी।

सवाल हुआ कि क्या जोहरान

ममदानी ने भारत की अदालतों में जाँच एजेंसियों के ज़रिये जमा दस्तावेज़ जो उमर ख़ालिद को मुजरिम ठहराने के लिए जमा किये गए थे उनको पढ़ा है ? और क्या Agencies 5 साल का लम्बा वक़्त गुज़र जाने के बाद भी इनको मुजरिम ठहराने के लिए दस्तावेज़ इकट्ठे नहीं कर पाई ?

जवाब यह दिया जाता है के जिस आरोपी को अपने बेगुनाह होने का मौका ही न मिला हो, उसको लगातार 1800 दिनों से ज़्यादा जेल में कैद रखा हो। इसके बाद जांच एजेंसियों के दस्तावेज़ देखने की ज़रूरत कहाँ बचती है। उसके बाद उमर की गिरफ्तारी कितनी सही और ग़लत का अंदाज़ा खुद बखुद लगाया जा सकता है।

यूँ तो हालिया दिनों में भारतीय न्यायिक प्रक्रिया में कई ऐसे बड़े फैसले देश और दुनिया के सामने आ चुके हैं जो या तो आस्था की बुनियाद पर दिए गए थे या फिर सरकारी दबाव में।

कई दुसरे सांसदों ने भी उमर ख़ालिद के मामले में एकजुटता दिखाते हुए उसकी ज़मानत की मांग रखी है।

अमेरिकी सांसद जिम मैकगवर्न जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं और जेमी रस्किन द्वारा अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय मोहन क वात्रा को लिखे पत्र में ख़ालिद को ज़मानत देने की अपील की गई है। साथ ही ख़ालिद का जुडिशल ट्रायल शुरू किए जाने की भी मांग की गई है।

मैकगवर्न और रस्किन के अलावा, पत्र पर डेमोक्रेटिक सांसद क्रिस वैन होलेन, पीटर वेल्च, प्रमिला जयपाल, जैन शाकोव्स्की, रशीदा तालिब और लॉयड डॉगेट के हस्ताक्षर शामिल हैं।

सांसदों ने कहा है कि ट्रायल शुरू हुए बिना ख़ालिद की लगातार बरसों की हिरासत अंतरराष्ट्रीय क़ानून के मानदंडों का उल्लंघन है। मैकगवर्न ने इस चिट्ठी को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर साज़ा किया है।

कारणों से सुनवाई में 55 बार से ज़्यादा देरी हुई है। उन्होंने इसे अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) का उल्लंघन बताया है।

सिब्ल का कहना है कि सरकार उमर ख़ालिद को सजा देने पर तुली हुई है और अदालतें मामले को अंतहीन रूप से खींचकर इसमें मदद कर रही हैं, जिसे अधिवक्ता कपिल सिब्ल ने 'अन्याय' का सबसे बड़ा रूप बताया है।

जेल की बुलंद दीवारों के अंदर सलाखों के पीछे JN के एक तालिबे इल्म और अमेरिका की सबसे घनी आबादी के शहर New York के city हॉल में शपथ लेने वाले Mayor के बीच रिश्तों की कहानी की हकीकत को समझने की कोशिश की तो पता चला दर्द सीनों में अभी ज़िंदा है।

अमेरिका के संसद भवन तक पहुँचने वाली मानवाधिकार की यह खबर दुनिया में ज़िंदा दिलों

लंबित मामलों की सूची बहुत लम्बी है, आपको मालूम है भारत की Courts कुल लंबित मामले कितने हैं ? सभी स्तरों पर देखा जाए तो 5 करोड़ 25 लाख से ज़्यादा मामले पेंडिंग हैं, जिसमें से 4 करोड़ 6 लाख से ज़्यादा मामले निचली अदालतों में हैं।

उच्च न्यायालयों में 63 लाख से ज़्यादा मामले लंबित हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट में से ज़्यादा मामले सितंबर 2025 तक लंबित पड़े हुए हैं। आपको बता दें High courts और Sub-Ordinate Courts में 32 लाख से ज़्यादा मामले 10 सालों से ज़्यादा समय से पेंडिंग हैं।

अदालतों में जजों, न्यायिक अधिकारियों और अन्य न्यायिक कर्मचारियों की भारी कमी इसकी वजह बताई जाती है, जिससे मामलों का निपटारा नहीं हो पा रहा है। इस तरफ किसी सरकार का कोई ध्यान नहीं गया है, और जाए भी क्यों सरकार में बैठे लोगों को तो इंसान मिल ही जाता है।

बल्कि यूँ कहें न्याय उनकी बपौती होती है, और अक्सर सरकार में बैठे लोगों पर जुर्म के सुबूत के बावजूद बरी कर दिया जाता है। इसकी घटनाएं आम तौर पर सामने आती ही रहती हैं। उन्नाव रेप मामले के मुल्जिम कुलदीप सिंह सेंगर की ताज़ा मिसाल सामने है।

हर साल बड़ी संख्या में नए मामले दर्ज होते हैं, जिससे अदालतों पर दबाव बढ़ता है। राष्ट्रीय लोक अदालतों के ज़रिए बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा किया जाता है, लेकिन यह कुल मुकदमों की पेंडेंसी के मुक़ाबले बहुत कम है।

ऐसे में उमर ख़ालिद और उनके साथियों के लिए दुनिया भर में इनको बरी किये जाने की मांग उठने लगी है। जाहिर है यह मामला अब सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। देखना यह है कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव में इंसान करती है या संवैधानिक तरीके से उमर ख़ालिद उनके साथियों और इन जैसे लाखों बेगुनाह आरोपियों को कब तक इंसान दे पाती है।



ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री के दोस्त के मुल्क के राजनेता की चिट्ठी जिसको भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना जा रहा है, उसके अमेरिका में क्या मानी निकाले जा रहे हैं। भारत के परिपेक्ष में ट्रंप की नीतियों के कारण पहले से ही भारत-अमेरिका संबंधों में काफी खटास आ चुकी है, New York मेयर के लेटर से रिश्तों में और दरार बढ़ जाने के इमकान बढ़ गए हैं।

लेकिन याद रहे ममदानी अकेले नेता नहीं हैं जो उमर ख़ालिद की हिमायत में आये हैं, उनके अलावा अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के

याद रहे उमर ख़ालिद को दिल्ली दंगों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, इतिफ़ाक़ यह है कि उन्हीं दिनों अमेरिकी ट्रम्प भी भारत के दौरे पर थे जब दिल्ली सांप्रदायिक दंगों में जल रहा था। शर्मनाक यह है कि दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी को बरी कर दिया गया था और वो NCT दिल्ली के कानून एवं न्याय मंत्री का पद भार संभाल रहे हैं।

उमर ख़ालिद के वकील कपिल सिब्ल ने कहा कि प्रशासनिक चूक, स्टाफ की कमी और जांच अधिकारी की अनुपस्थिति जैसे

की दास्ताँ को बयाँ करती है। अगर यह दर्द जोहरान ममदानी तक सीमित होता तो इसको रसूल की हदीथ अनुवाद: 'यकीनन मोमिन (आपस में) भाई-भाई हैं।' से जोड़ लेते लेकिन वहां तो कई अमेरिकी ईसाई सांसद और मानवाधिकार संस्था के चेयरमैन इंसान की इस लड़ाई में शामिल हो चुके हैं।

हालांकि यह सवाल भी हो रहा है कि ये सांसद ग़ाज़ा के मासूमों पर होने वाले तारीख़ के बदतरीन जुल्म और नाइंसाफी के दौरान कहाँ थे ?

हालांकि देश की अदालतों में

वेनेजुएला पर भिड़े अमेरिका और चीन, राष्ट्रपति मादुरो की रिहाई पर ड्रेगन का अल्टीमेटम

बता दें कि चीन के विदेश मंत्रालय ने रविवार, २ जनवरी २०२६ को जारी अपने बयान में कहा है कि अमेरिका को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करना चाहिए और इस पूरे मामले का समाधान बातचीत और कूटनीतिक संवाद के जरिए किया जाना चाहिए हैं। मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर जारी बयान में साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका को न सिर्फ मादुरो दंपति की व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, बल्कि उनकी जबरन कार्रवाई और निर्वासन को भी तुरंत रोकना चाहिए।



गौरतलब है कि चीन ने इस कदम को अंतरराष्ट्रीय कानून और स्थापित वैश्विक मानदंडों का उल्लंघन बताया है। मौजूद जानकारी के अनुसार, चीनी विदेश मंत्रालय का कहना है कि किसी संप्रभु देश के

निर्वाचित राष्ट्रपति के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई वैश्विक व्यवस्था के लिए खतरनाक मिसाल बन सकती है।

अपने आधिकारिक बयान में चीन ने अमेरिका से अपील की है कि वह वेनेजुएला की सरकार को गिराने की कोशिशें बंद करे और वहां के राजनीतिक संकट को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की दिशा में कदम उठाए हैं। चीन ने अमेरिकी कार्रवाई को सीधे तौर पर अंतरराष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन करार दिया है और इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बताया।

बता दें कि वेनेजुएला लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और अंतरराष्ट्रीय दबाव का सामना कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका और चीन के आमने-सामने आने से यह मुद्दा अब केवल लैटिन अमेरिका तक सीमित न रहकर वैश्विक भू-राजनीतिक टकराव का हिस्सा बनता जा रहा है। जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस पर संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी तीखी बहस देखने को मिल सकती है, जो वैश्विक कूटनीति की दिशा को प्रभावित कर सकती है।

जयशंकर को चीन पर कौन सी चिट्ठी मिली

पाकिस्तान में एक इलाका है बलूचिस्तान। हालातों को देखते हुए कुछ एक्सपर्ट्स कहने लगे हैं कि हो सकता है किसी दिन ये दुनिया का 196 देश बन जाए। बहरहाल बलूचिस्तान के नेता मीरियार बलोच ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक ओपन लेटर लिखा है। इस चिट्ठी में बलोच नेता ने चेतावनी देते हुए कहा कि चीन आने वाले महीनों में बलोचिस्तान में सेना तैनात कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बलोचियों के साथ-साथ भारत के लिए भी यह खतरे की घंटी है। लेटर में कहा गया कि अगर बलूचिस्तान की रक्षा और सेनाओं की क्षमता को और मजबूत नहीं किया गया और उन्हें पुराने तौरतरीकों के अनुसार अनदेखा नहीं किया जा रहा है तो यह पूरी तरह संभव है।

NOTICE:

Times of Pedia does not guarantee, directly or indirectly, the quality or efficacy of any product or services described in the advertisements or other material which is commercial in nature in this Newspaper. Furthermore, Times of Pedia assumes no responsibility for the consequences attributable to inaccuracies or errors in the printing of any published material from the news agencies or articles contributed by readers. It is not necessary to agree with the views published in this Newspaper. All disputes to be settled in Delhi Courts only.

ईरान में विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या 15 हुई

ईरान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के कारण भड़के विरोध-प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में कम से कम 15 लोगों की मौत हो चुकी है। एक मानवाधिकार एजेंसी ने यह जानकारी दी।

अमेरिका स्थित 'ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी' ने रविवार सुबह बताया कि ईरान के 31 प्रांतों में से 25 प्रांतों में 170 से अधिक स्थानों पर प्रदर्शन हुए हैं। उसने बताया कि मरने वालों की संख्या कम से कम 15 हो गई है और 580 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच, ईरान के सर्वोच्च नेता ने देश में अशांति उत्पन्न करने वाले विरोध प्रदर्शनों को लेकर कहा कि "दंगाइयों पर सख्ती करनी होगी।"

सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की ये टिप्पणियां एक सप्ताह से जारी प्रदर्शनों के प्रति अधिकारियों को अधिक



आक्रामक रुख अपनाने की अनुमति देने का संकेत प्रतीत होती हैं। विरोध-प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा के संबंध में 86 वर्षीय अयातुल्ला अली खामेनेई की यह पहली टिप्पणी है।

विरोध-प्रदर्शन का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर तेहरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा करता है, तो अमेरिका 'उनको बचाने के लिए आगे आएगा।' यह

हालांकि, अभी स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप हस्तक्षेप करेंगे या नहीं और यदि करेंगे तो कैसे करेंगे लेकिन उनकी टिप्पणियों को लेकर ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया दी।

ईरान के अधिकारियों ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने की धमकी दी। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब ट्रंप ने शनिवार को कहा कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया है।

मादुरो तेहरान के लंबे समय से

सहयोगी रहे हैं। यह खूब के बाद से ईरान में सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है। पुलिस हिरासत में खूब वर्षीय महसा अमीनी की मौत के बाद देशव्यापी प्रदर्शन हुए थे। अमीनी को अधिकारियों ने हिजाब न पहनने के कारण हिरासत में लिया था।

खामेनेई ने कहा, "हम प्रदर्शनकारियों से बात करते हैं, अधिकारियों को भी उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन दंगा करने वालों से बात करने का कोई फायदा नहीं है। दंगा करने वालों को उनकी जगह दिखानी होगी।"

उन्होंने ईरान के अधिकारियों द्वारा लगातार किए जाने वाले एक दावे को भी दोहराया कि इजराइल या अमेरिका जैसी विदेशी ताकतें विरोध प्रदर्शनों को बढ़ावा दे रही हैं लेकिन उन्होंने इसका कोई सबूत नहीं दिया। उन्होंने ईरान के रियाल के गिरते मूल्य के लिए भी "दुश्मन" को दोषी ठहराया।

उत्तर कोरिया ने समुद्र में दागी बैलिस्टिक मिसाइल: दक्षिण कोरिया

उत्तर कोरिया ने समुद्र में रविवार को एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। दक्षिण कोरिया की सेना ने यह जानकारी दी। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा कि उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से मिसाइल प्रक्षेपण रविवार सुबह किया लेकिन उसने इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं दी।

जापान के रक्षा मंत्रालय ने भी उत्तर कोरिया द्वारा संदिग्ध मिसाइल प्रक्षेपण किए जाने की सूचना दी है। इस प्रक्षेपण के कारण किसी प्रकार का नुकसान



होने की तत्काल कोई जानकारी नहीं मिली है। यह प्रक्षेपण उत्तर कोरिया में सत्तारूढ़ 'वर्कर्स पार्टी' की आगामी कांग्रेस (पार्टी की सर्वोच्च स्तर की बैठक) से पहले हथियारों का प्रदर्शन करने



की ताजा घटना है।

विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर कोरिया कांग्रेस से पहले रक्षा क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां दिखाने के लिए हथियार परीक्षणों में तेजी ला सकता है। पर्यवेक्षक इस बात

पर नजर रख रहे हैं कि क्या उत्तर कोरिया अमेरिका के प्रति कोई नयी नीति निर्धारित करेगा और लंबे समय से ठप पड़ी वार्ता को फिर से शुरू करने के उसके आह्वान पर प्रतिक्रिया देगा।

यह प्रक्षेपण दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग के चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ शिखर वार्ता के लिए चीन खाना होने से कुछ घंटे पहले हुआ। इस सप्ताह की शुरुआत में उत्तर कोरिया ने कहा था कि उसने समुद्र में लंबी दूरी की रणनीतिक क्रूज मिसाइल दागी हैं।

Jamaat-e-Islami Hind Calls for 2026 to be the “Year of Justice, Peace, Unity and Inclusive Sustainable Development for All”

New Delhi: Jamaat-e-Islami Hind (JIH) held its press conference on 03 January 2026, during which the organisation articulated serious concerns on rising communal polarisation, winter distress among the poor, and targeted violence against religious and regional minorities.

Addressing the press, Prof. Salim Engineer, Vice President of JIH said India has always been a deeply religious country with a rich legacy of coexistence and communal harmony. “By and large, our religious leaders and institutions have played a pivotal role in promoting unity in diversity. However, this legacy is under threat,” he said. He expressed grave concern over the rise in communal rhetoric, Islamophobia, hate speeches, mob lynching, and religious discrimination.

Quoting the South Asia Justice Campaign’s India Persecution Tracker for 2025, Prof. Engineer said the report reveals “a sharp escalation in state and non-state abuses against religious minorities, mainly Muslims,” including extrajudicial killings, mob violence, arbitrary deten-



tions, punitive demolitions, rampant hate speech, and forced deportations. He noted that these patterns intensified after a major terror incident, leading to reprisals, mass arrests under pretexts such as cow protection and security threats, and heavy casualties among Adivasis in counter-insurgency operations.

“It cannot be denied that certain forces are misusing religion for political benefits by creating a chasm between religious communities through communal polarization,” Prof. Engineer said. At the same time, he asserted confidence in the moral strength of society, stating,

“We feel that the people of India have the strength and wisdom to overcome and defeat the communal forces in our country.”

Prof. Salim Engineer highlighted that Jamaat-e-Islami Hind has been working tirelessly through interfaith and peace initiatives such as Dharmik Jan Morcha and Sadbhavna Manch. “These platforms have been instrumental in bringing people together to engage in dialogue, understand one another, and build bridges of unity,” he said. He announced that to redouble these efforts, Jamaat-e-Islami Hind has resolved to make 2026 the “Year of Justice, Peace, Unity

and Inclusive Sustainable Development for All,” calling it an opportunity to reaffirm commitment to social harmony, justice, brotherhood, and a better future for all citizens.

Speaking on winter distress, the JIH Vice President Malik Motasim Khan said Jamaat-e-Islami Hind, in collaboration with like-minded organisations, is actively supporting the poor and homeless through widespread blanket distribution drives across northern and eastern India. He said these efforts respond to severe cold waves that disproportionately affect vulnerable populations living in open spaces and inadequate shelters. “Warm blankets are provided to those in need, regardless of religion, caste, or background,” he said.

He urged the Government of India to take proactive and coordinated action during winter, including expanding night shelters, distributing warm clothing, providing hot meals, deploying mobile health units, and strengthening early warning systems. He also appealed to citizens to contribute through dona-

tions, volunteering, and community care so that “no one is left unprotected during harsh winter conditions.”

Malik Moatasim Khan expressed deep alarm over the surge in targeted violence and harassment against Christian communities across various regions of India. “We stand in solidarity with the Christian community in this hour of crisis,” he said. He warned that incidents such as disruption of prayer meetings, burial-related disputes, and allegations under anti-conversion laws risk creating an atmosphere of anxiety and mistrust if left unaddressed.

Malik Moatasim Khan also strongly condemned the horrific lynching of Anjel Chakma, a young MBA student from Tripura, describing it as “a hate crime rooted in racial prejudice and a result of sustained discrimination and othering of our fellow citizens from the Northeast.” He said such attacks expose a failure of society and weaknesses in law enforcement that allow anti-social elements to feel immune.

Police notices to JNUSU leaders spark row

NEW DELHI: The Jawaharlal Nehru University Students’ Union (JNUSU) on Saturday accused the university administration of targeting student representatives after Delhi Police issued enquiry notices to current and former union office bearers over protests against surveillance

measures at the university’s central library. According to an official statement, the notices followed an FIR filed by the JNU administration against JNUSU president Aditi Mishra, vice president Gopika, general secretary Sunil, joint secretary Danish and former JNUSU president Nitish Kumar.

Two accused involved in ATM fraud arrested

NEW DELHI: Delhi Police on Saturday arrested two accused allegedly involved in ATM fraud in the South-West District. The arrests were made by the staff of Kishangarh Police Station as part of intensified patrolling and surveillance to curb crime and ensure the safety and security of residents.

According to a statement released by the South-West District police, the arrested accused have been identified as Salman, son of Kabir, and Salman, son of Usman. With their arrest, the police recovered one country-made pistol (desi katta), two live cartridges, Rs 12,700 in cash, four ATM jamming devices.

Defence Minister unveils portraits of Vajpayee, Madan Mohan Malaviya at Assembly

NEW DELHI: Defence Minister Rajnath Singh said on Saturday that no nation becomes great merely through resources, technology, or economic strength, but its true strength lies in the ideals it adopts as the foundation of its life-values and the personalities it holds as its role models.

Unveil portraits of Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee and Bharat Ratna Pandit Madan Mohan Malaviya at the Delhi Legislative Assembly, Rajnath Singh said, “Ideals are not merely objects of remembrance, but guiding inspirational forces.”

“That is why, in the tradition of our ideals, along with Ram, Krishna, Buddha, and Mahavira, we also include Mahamana Malaviya Ji and the



revered Atal Ji,” he said.

The Defence Minister said, “Atal Ji taught us how to remain humble even while in power and how to serve the nation’s interests even while in the Opposition. His life teaches us that the beauty of democracy lies not in differences of opinion, but in the manner of resolving them.”

He said, “Here, in the historic precincts of the Delhi Legislative

Assembly, we are celebrating the birth centenary of India’s former Prime Minister, Atal Bihari Vajpayee. During the ceremony, the portraits of Atal Bihari Vajpayee and Pandit Madan Mohan Malaviya were also unveiled. I pay my heartfelt tribute to these great leaders and bow in respect to their memory.”

The portraits were installed in the Assembly

House as a lasting tribute to the monumental contributions of these two national icons to India’s democracy, education, culture and public life, said Speaker Vijender Gupta.

The programme witnessed the release of a coffee table book titled ‘Bharat Mata’, which presents Indian nationalism as expressed through painting, architecture and literature, he said.

CM Rekha Gupta orders free packed sugar for 65,883 Antyodaya families

NEW DELHI: Delhi Chief Minister Rekha Gupta has approved the free distribution of branded sugar packs to all beneficiaries under the Antyodaya Anna Yojana (AAY), an official said on Saturday.

The decision was taken by CM Gupta-chaired Delhi Cabinet meeting.

It is aimed to serve as a New Year gift from the Chief Minister for the poor and marginalised sections, the official said in a statement.

The scheme will be implemented from January 2026 to March 2027, covering a total period of 15 months, ensuring sustained support and enhanced food security for the most vulnerable sections.

Sharing details of the decision, Chief Minister Gupta said that under this initiative, all AAY beneficiaries in Delhi



will be provided one kilogram of sugar per month, free of cost, in properly branded and standardised packets.

This initiative marks another concrete step in the Delhi government's pro-poor policies, ensuring both food security and access to quality supplies.

At present, sugar is distributed in loose form through fair price shops, which often leads to issues such as dust, moisture, contamination and short weighing.

The shift to one kg packaged and branded

packets will ensure improved hygiene, safe storage, ease of handling and accurate measurement. As per official estimates, 65,883 AAY families in Delhi will benefit from the scheme, with each eligible household receiving one kg of sugar per month.

Until the finalisation and approval of a new tender for branded packaging, distribution will continue under the existing system to ensure uninterrupted supply to beneficiaries.

Chief Minister Gupta said that the Delhi gov-

ernment is working in line with the vision of Prime Minister Narendra Modi, who has consistently placed the welfare of the poor at the centre of governance.

She added that the Delhi government remains committed to translating this vision into tangible outcomes through sustained efforts for the upliftment of the poor and disadvantaged.

The Chief Minister said that this commitment is reflected in initiatives such as affordable and nutritious meals through Atal Canteens, housing for economically weaker families, free ration, and accessible healthcare services.

The Delhi government firmly believes that no needy citizen should be deprived of basic necessities and essential public services.

CRIME

Interstate arms trafficker arrested, 2 pistols seized

NEW DELHI : Delhi Police have arrested an alleged illegal arms supplier from the Shastri Park area of northeast Delhi and recovered two sophisticated pistols and six live cartridges from his possession, an official said on Saturday.

The accused has been identified as Ankit (26), also known as Munna, a resident of Ghaziabad in Uttar Pradesh. Police said he is allegedly linked to an interstate arms trafficking racket operating in the Delhi-NCR region. According

to police, Ankit revealed during interrogation that he entered the illegal arms trade after being released from jail and was supplying firearms across Delhi-NCR.

He also disclosed that he procured weapons from another supplier identified as Sonu alias Kale. Deputy Commissioner of Police (Crime) Aditya Gautam said police received specific inputs on January 2 about an arms supplier expected to arrive near Shastri Park Metro Station.

Man shot dead in property dispute in Narela

NEW DELHI: A 55-year-old man was allegedly shot dead following a property-related dispute in outer north Delhi's Narela area, police said on Saturday. Two men have been taken into custody in connection with the incident.

Police said the case came to light when Dinesh Kumar, a resident of Ghoga village, along with Bhoop Singh, walked into Narela police station and claimed he had shot Dharampal, a resident of the same village, using his licensed

revolver over a dispute linked to property-sale commission. A police team accompanied the accused to the spot, where Dharampal's body was recovered from near a tubewell in Ghoga village.

The body was identified by the victim's son, Pradeep, while crime team and forensic science laboratory officials examined the scene and collected evidence. A case has been registered under relevant sections of the Bharatiya Nyaya Sanhita and the Arms Act.

3 held for high-value burglary in South Delhi

NEW DELHI: Delhi Police have arrested three people in connection with a high-value burglary at the residence of an elderly woman in south Delhi and recovered stolen jewellery, cash and a scooter worth over 30 lakh, officials said on Saturday.

The accused have been identified as Ishaq alias Kalua (24), Pawan (26) and Bharat alias Vicky (23). Police said Pawan and Bharat are listed as active "bad characters" of Ambedkar Nagar police station.

The burglary was

reported on January 1 after the woman returned home in the morning to find the main gate handle broken and household items scattered.

Her complaint stated that gold and silver jewellery accumulated over her lifetime, along with cash, had been stolen.

Police registered a case under relevant sections of the Bharatiya Nyaya Sanhita and analysed CCTV footage, which showed three suspects entering the house around 3 am with their faces covered.

Riots case: SC to deliver verdict on bail pleas of accused on Jan 5

NEW DELHI: The Supreme Court will on Monday pronounce its decision on the bail pleas of seven accused, including student activists Umar Khalid and Sharjeel Imam, in the alleged "larger conspiracy" case linked to the 2020 Delhi riots.

As per the causelist published on the website of the Apex Court, a Bench of Justices Aravind Kumar and Prasanna B. Varale will deliver the judgment on January 5.

The bail pleas have been filed by Umar Khalid, Sharjeel Imam, Gulfisha Fatima, Meeran Haider, Shifa-ur-Rehman, Shadab Ahmed, and Mohd.

Saleem Khan, facing charges under the stringent Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), has been in custody for more than five years.

Earlier, on December 10, the Supreme Court had reserved its verdict on the batch of special leave petitions (SLPs) challenging the Delhi High Court's refusal to grant bail to the accused in the 2020 riots "larger conspiracy" case.

After hearing both sides, the Justice Kumar-led Bench directed the petitioners as well as the



prosecution to file any additional documents in support of their submissions by December 18.

Opposing the bail pleas, Solicitor General (SG) Tushar Mehta, appearing for the Delhi Police, had contended that the violence was not a spontaneous communal clash but a "well-designed, well-crafted, orchestrated and preplanned" attack on the sovereignty of the nation.

"This was not a spontaneous act of violence; this was an attack against the sovereignty of the nation," the SG had argued, relying on speeches, WhatsApp chats and other material to claim a "clear and discernible attempt to divide the society on communal lines".

He had argued that the delay in the trial proceedings was attributable to the accused since they were "not cooperating" and "each of them argued for 4-5 days for opposing framing of charges".

"Now, in all cases where it's difficult to defend on facts, the mechanism is to delay the trial and not to go into the merits and say 'give me bail'. This has become a pattern," SG Mehta added.

Earlier, on September 2, last year, the Delhi High Court had dismissed the bail pleas of Khalid, Imam and several other accused in the case, observing that a prima facie case under the UAPA was made out against them.

सदन में हंगामा, केजरीवाल से माफी की मांग

दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार को शुरू होते ही हंगामेदार हो गया। सत्र के दूसरे दिन, मंगलवार को भी सदन की कार्यवाही की शुरुआत आवारा कुत्तों की गिनती के मुद्दे पर जोरदार हंगामे के साथ हुई।

भाजपा के विधायक अजय महावर ने सदन में इस मुद्दे को उठाते हुए आम आदमी पार्टी (आप) पर भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाया। महावर ने मांग की कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस मामले में माफी मांगनी चाहिए। सदन में बढ़ता हंगामा और गरमागरमी को देखते हुए, विधानसभा अध्यक्ष को सदन



की कार्यवाही को 5 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। दोबारा बैठक शुरू होने पर विधानसभा में फिर हंगामा होने लगा। जिसे देखते हुए एक बजे तक बैठक स्थगित कर दी गई।

इस मुद्दे पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने केजरीवाल को पत्र लिखा है। जिसमें आशीष सूद ने अरविंद केजरीवाल पर भ्रामक और तथ्यहीन बयान देने का आरोप

लगाते हुए इसे अफवाह फैलाने वाला बताया है। आशीष सूद ने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। केजरीवाल को लिखे एक लेटर में मंत्री ने कहा, 'आपने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया है कि टीचरों को आवारा कुत्तों की गिनती से जुड़ी ड्यूटी दी जा रही है। ये दावे न सिर्फ गलत हैं।

ट्रम्प की तरह पाकिस्तान से आतंकियों को लाएं मोदी, असदुद्दीन ओवैसी की मांग पर भड़की बीजेपी

वेनेजुएला में अमेरिकी सेना के 'सर्जिकल स्ट्राइक' और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी की गूंज अब भारतीय राजनीति में भी सुनाई दे रही है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस घटना का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है।

एक रैली के दौरान ओवैसी ने कहा कि यदि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरे देश में घुसकर मादुरो को न्यूयॉर्क ला सकते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी को भी पाकिस्तान जाकर ख/क्व मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड को भारत वापस लाना चाहिए। ओवैसी ने

चुनौती देते हुए कहा, 'मोदी जी, आप भी पाकिस्तान जाकर मसूद अजहर और लश्कर के उन शैतानों को वापस ला सकते हैं जिन्होंने मुंबई के खिलाफ साजिश रची थी।'

ओवैसी के इस तीखे बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने हमेशा आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया, 'हम एक जिम्मेदार राष्ट्र और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं। भारत अपने पड़ोसियों के साथ

सौहार्दपूर्ण संबंध चाहता है और हम किसी के उकसावे में आकर कार्रवाई नहीं करते।' खटाना ने जोर देकर कहा कि भारत की रणनीति देशों को नहीं, बल्कि सीधे तौर पर आतंकवाद के अड्डों को निशाना बनाने की रही है।

वहीं, बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने ओवैसी के बयान पर तंज कसते हुए इसे केवल 'सनसनी फैलाने की कोशिश' करार दिया। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि ओवैसी अब अमेरिकी राष्ट्रपति को सलाह देने लगे हैं और वे प्रार्थना करते हैं कि ट्रंप उनकी बातों पर विचार करें।

राम रहीम का 'पैरोल गेम' फिर शुरू, हत्या-रेप का दोषी 15वीं बार जेल से आएगा बाहर

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को एक बार फिर 40 दिन की पैरोल मिल गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से रविवार को यह जानकारी दी। राम रहीम फिलहाल रोहतक की सुनारिया जेल में अपनी दो शिष्याओं के बलात्कार और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में 10 साल की सजा काट रहा है।

हाल के वर्षों में राम रहीम को मिलने

वाली पैरोल की आवृत्ति ने एक नई बहस छेड़ दी है। यह ताजा पैरोल पिछले साल अगस्त में मिली 6 दिनों की छुट्टी के कुछ ही महीनों बाद मिली है। पिछले एक साल के रिकॉर्ड पर गौर करें तो उसे जनवरी में 5 दिन, अप्रैल में 5 दिन (फरलो) और अगस्त में 6 दिन की रिहाई मिल चुकी है। खस्त्र में दोषी ठहराए जाने के बाद से यह क्वीं बार है जब डेरा प्रमुख को जेल से अस्थायी रिहाई मिली है।

राम रहीम की बार-बार होने वाली रिहाई पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जैसे सिख संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई है। इन संगठनों का आरोप है कि एक गंभीर अपराधी को बार-बार पैरोल देना कानून की भावना के खिलाफ है। आलोचकों का यह भी मानना है कि चुनावों के आसपास राम रहीम की रिहाई अक्सर राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बन जाती है, क्योंकि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों

में डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों की संख्या काफी अधिक है।

विशेष रूप से हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र और हिसार जैसे जिलों में डेरा का अच्छा-खासा प्रभाव है। प्रशासन का कहना है कि पैरोल जेल नियमों के तहत दी जाती है, लेकिन बार-बार जेल से बाहर आने की इस प्रक्रिया ने कानूनी विशेषज्ञों और विपक्षी दलों के बीच सवाल खड़े कर दिए हैं।

SUBSCRIPTION FORM

TIMES OF PEDIA

Issue	Subscription Price	Years
52	250/-	1
104	500/-	2
260	1,300/-	5
520	2,600/-	10
--	5,000/-	Life

Name :.....
Address :.....
.....
Email:.....
Contact Phone No.....
for donation ☐ /life ☐ /10 yrs ☐ /5 yrs ☐ subscription
The sum of Rupees..... (Rs...../-)
through cheque/DD No.....dt.....

Fill the above form neatly in capital letters and send it to us on the following address :
Times of Pedia, K-2-A-001, Abul Fazal Enclave-I,
Jamia Nagar, Okhla, New Delhi-110025
or email : timesofpedia@gmail.com

Also Send us your subscription, membership, donation amount in favour of Times of Pedia, New Delhi
Punjab National Bank, Nanak Pura Branch,
New Delhi-110021
A/C No.1537002100017151, IFS Code : PUNB 0153700



“First, they ignore you, then they laugh at you, then they fight you and then you win.”
- Mahatma Gandhi

ADVERTISEMENT TARIFF

TIMES OF PEDIA

Size/Insertion Single	B&W (Rs)	4 Colour (Rs)
Full Page (23.5 x 36.5 cm)	30,000/-	1,00,000/-
A4 (18.7 x 26.5 cm)	20,000/-	60,000/-
Half Page (Tall-11.6 x 36.5 cm)	18,000/-	50,000/-
Half Page (wide-23.5 x 18 cm)	8,000/-	50,000/-
Quarter Page (11.6 x 18 cm)	10,000/-	28,000/-
Visiting Card size (9.5 x 5.8 cm)	3,000/-	10,000/-

MECHANICAL DATA:
Language: English, Hindi and Urdu
Printing: Front and Back - 4 Colours , Inside pages - B&W
No. of Pages: 12 pages (more in future)
Price: Rs. 3/-
Print order: 25,000
Periodicity: Weekly
Material details: Positives/Format of your advertisements should reach us 10 days before printing.
Note: 50% extra for back page, 100% extra for front page
Please Add Rs. 10 for outstation cheques.
50% advance of total add cost would be highly appreciable, in case of one year continue add. Publication cost will reduce 50% of actual cost.

Bank transactions details of TIMES OF PEDIA
Send your subscriptions/memberships/donations etc.
(Cheques/DD) in favour of TIMES OF PEDIA New Delhi
Punjab National Bank, Nanak Pura Branch , New Delhi-110021
A/C No.1537002100017151, IFS Code : PUNB 0153700

क्या दिल के लिए खतरनाक है रेड मीट?

हाल ही में फोर्टिस वसंत कुंज के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉ. शुभम वत्स ने अपने इंस्टाग्राम पर रेड मीट से जुड़े कुछ मिथकों पर बात की है। डॉ. वत्स के अनुसार, अगर रेड मीट को सही मात्रा में और सही तरीके से खाया जाए तो यह कई मायनों में फायदेमंद हो सकता है।

रेड मीट को लेकर लोगों के बीच काफी कन्फ्यूजन रहता है। कुछ लोग इसे सेहत के लिए नुकसानदायक मानते हैं और दिल की बीमारी से जोड़ देते हैं, जबकि कुछ इसे पूरी तरह डाइट से हटा देते हैं। लेकिन क्या वाकई



रेड मीट इतना नुकसानदेह है, या फिर इसके बारे में फैली बातें सिर्फ मिथक हैं? फोर्टिस वसंत कुंज के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट डॉ. शुभम वत्स ने हाल ही में रेड मीट से जुड़े मिथकों पर बात की है। डॉ. वत्स के

अनुसार, भारत में यह सबसे बड़ा मिथक है कि रेड मीट खाने से हार्ट अटैक होता है। उनका कहना है कि अगर रेड मीट को सही तरह से और सही तरीके से खाया जाए तो यह सेहत के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। रेड मीट को छोड़ने की

नहीं, बल्कि सही से खाने की जरूरत है। डॉ. वत्स चेतावनी देते हुए कहते हैं कि प्रॉसेस्ड रेड मीट जैसे सॉसेज, बेकन और सालामी खाने से हार्ट की बीमारी और टाइप २ डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। वे सलाह देते हुए कहते हैं कि हमेशा बिना प्रोसेस वाले, पतले (लीन) कट के लाल मांस को चुनें और इसे हफ्ते में एक-दो बार, हथेली जितने हिस्से तक ही लें। जब भी रेड मीट खाएं, उसके साथ फाइबर वाली चीजें डाइट में जरूर शामिल करें ताकि आपका खाना हेल्दी और बैलेंस में रहे।

बेसन का चिल्ला या गेहूं की रोटी, वजन घटाने के लिए क्या खाएं?

आज के दौर में जहां हर दूसरा व्यक्ति अपने बढ़ते वजन से परेशान है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि क्या खाया जाए, जिससे शरीर को भरपूर पोषण भी मिले और वजन घटाने में भी मदद मिले। आज हम इस खबर में जानेंगे कि गेहूं की रोटी और बेसन चिल्ला में से वजन घटाने में कौन ज्यादा मददगार हो सकता है।

आज के दौर में वजन बढ़ना एक आम समस्या बन गया है। जब वजन घटाने की बात आती है तो लोगों को लगता है कि इसके लिए उन्हें स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी होगी या कम खाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। सिर्फ खाना छोड़ने से ही वजन कम नहीं होता, बल्कि सही खाना चुनना भी उतना ही जरूरी होता है। भारतीय घरों में गेहूं की रोटी रोज खाई जाती है, वहीं बेसन से बना चिल्ला आजकल काफी ट्रेंड में है और इसे हल्का व प्रोटीन से भरपूर ऑप्शन माना जाता है। ऐसे में



आज हम इस खबर में जानेंगे कि वजन घटाने के लिए रोटी और बेसन चिल्ला में से क्या बेहतर है और क्यों। एक सामान्य गेहूं की रोटी में कैलोरी होती हैं जो इसके साइज पर डिपेंड करती हैं और यह शरीर को जरूरी कार्बोहाइड्रेट और फाइबर भी देता है। वहीं, बेसन चिल्ले में लगभग १०० कैलोरी होती है लेकिन इसमें प्रोटीन और थोड़ी मात्रा में हेल्दी फैट भी होती है। वजन घटाने में कैलोरी के साथ-साथ पोषण की क्वालिटी भी बहुत मायने रखती है। बेसन चिल्ला प्रोटीन से भरपूर होता है क्योंकि बेसन चने से



बनता है। प्रोटीन पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और मसल्स बनाने में मदद करता है जिससे मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। वहीं गेहूं की रोटी हेल्दी जरूर है लेकिन इसमें बेसन चिल्ले के मुकाबले प्रोटीन कम होता है। पेट भरने के मामले में बेसन चिल्ला अक्सर बेहतर साबित होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। चिल्ला खाने के बाद जल्दी भूख नहीं लगती जिससे आप ओवरईटिंग से बचते हैं जो वजन बढ़ने का एक बड़ा कारण है। वहीं रोटी हल्की होती है, इसलिए इसे दाल या सब्जी के साथ खाना

बेहतर रहता है ताकि पेट लंबे समय तक भरा रहे। साबुत गेहूं की रोटी में अच्छी मात्रा में फाइबर होता है जो डाइजेशन को बेहतर बनाता है और बार-बार भूख लगने से बचाता है। वहीं, बेसन चिल्ले में भी फाइबर होता है लेकिन रोटी की तुलना में कम। बेसन चिल्ला और गेहूं की रोटी, दोनों ही हेल्दी हैं। हालांकि, ज्यादा प्रोटीन होने की वजह से बेसन चिल्ला वजन घटाने में थोड़ा ज्यादा मददगार हो सकता है। वहीं गेहूं की रोटी फाइबर और एनर्जी के मामले में बेहतर है। अगर आप हाई-प्रोटीन और पेट भरने वाला खाना चाहते हैं तो बेसन चिल्ला बेहतर है। अगर आप फाइबर और बैलेंस कार्ब्स वाला रोज का खाना चाहते हैं तो गेहूं की रोटी सही है। सबसे अच्छा तरीका है दोनों को अपनी डाइट में शामिल करें। नाश्ते या डिनर में चिल्ला और लंच में रोटी। इससे आपको प्रोटीन और फाइबर दोनों का फायदा मिलेगा।

किडनी को सॉलिड रखने के लिए पिएं ये, किडनी की सूजन और गंदगी होगी दूर

किडनी हमारे शरीर के लिए फिल्टर का काम करती है। यह शरीर की सारी गंदगी बाहर निकालती है और उसे हेल्दी रखती है। इसलिए हमें भी अपनी किडनी का ख्याल रखना चाहिए और ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए जो किडनी के स्वास्थ्य में इजाफा कर सकें।

किडनी हमारे शरीर का वो अंग है जो रूढ़ि धर्म का काम करता है ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। लेकिन खराब खानपान, लाइफस्टाइल जैसी बुरी आदतें हमारी किडनी को अंदर से डैमेज करती रहती हैं। ऐसे में यहां हम आपको एक ड्रिंक बता रहे हैं जो किडनी की प्राकृतिक

रूप से सफाई करने में मदद कर सकती है। हालांकि इसके साथ आपको हेल्दी डाइट का भी सेवन करना चाहिए, तभी आपको भरपूर फायदा मिलेगा। घर पर बनने वाली यह ड्रिंक बेहद असरदार है और इससे आपकी किडनी बुढ़ापे तक हेल्दी रह सकती है।

अमेरिका के नेशनल किडनी फाउंडेशन के अनुसार, हेल्दी, ऑलस्पाइस, इलायची, दालचीनी, लौंग, धनिया, जीरा, लहसुन पाउडर, अदरक, जायफल और काली मिर्च जैसे मसाले विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर होते हैं।

खेल समाचार

'टीम से बाहर कर दिया जाए तो...', KKR से बाहर होने पर बांग्लादेशी प्लेयर रहमान का पहला रिएक्शन



भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के निर्देश पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से पहले टीम से रिलीज कर दिया। हाल के राजनीतिक और सामाजिक विवादों के चलते यह फैसला लिया गया। मुस्ताफिजुर को केकेआर ने आईपीएल 2026 रुपये में खरीदा था।

आईपीएल 2026 सीजन से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स को बड़ा झटका लगा है। फ्रेंचाइजी ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज कर दिया है। यह फैसला केकेआर की ओर से नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के स्पष्ट निर्देश के बाद लिया गया है। पिछले कुछ हफ्तों से मुस्ताफिजुर रहमान की आईपीएल में भागीदारी को लेकर विवाद गहराता जा रहा था। हालात को देखते हुए बीसीसीआई ने हस्तक्षेप किया और केकेआर को उन्हें टीम से बाहर करने का निर्देश दिया। इस घटनाक्रम पर मुस्ताफिजुर का रिएक्शन सामने आया है।

टीम से बाहर किए जाने के बाद मुस्ताफिजुर रहमान ने बांग्लादेशी क्रिकेट वेबसाइट बीडीक्रिकटाइम से बातचीत में अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, 'अगर आपको टीम से बाहर कर दिया जाए, तो आप और क्या कर सकते हैं?' मुस्ताफिजुर रहमान को दिसंबर 2025 में हुए आईपीएल 2026 मिनी नीलामी में केकेआर ने 9 करोड़ 20 लाख रुपये में खरीदा था। शुरुआत में यह सौदा उनके क्रिकेट कौशल को लेकर चर्चा में रहा, लेकिन जल्द ही मामला मैदान से बाहर के विवादों में फंस गया। मुस्ताफिजुर की नियुक्ति के

बाद कुछ राजनीतिक संगठनों और धार्मिक समूहों ने इसका विरोध किया। यह विरोध खास तौर पर बांग्लादेश में हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं और वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर जताई गई चिंताओं के बाद तेज हुआ।

विवाद तब और बढ़ गया जब भारतीय जनता पार्टी के नेता कौस्तव बागची ने सार्वजनिक रूप से कोलकाता में आईपीएल मैचों में बांग्लादेशी खिलाड़ियों की मौजूदगी पर आपत्ति जताई। इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के सह-मालिक शाहरुख खान को लेकर भी राजनीतिक और सामाजिक हलकों में आलोचना शुरू हो गई।

हालांकि बीसीसीआई ने सीधे तौर पर राजनीतिक विवाद का उल्लेख नहीं किया, लेकिन बोर्ड ने हालात को देखते हुए एहतियाती कदम उठाया। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा, 'देश और आसपास के हालात को देखते हुए बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को निर्देश दिया कि वे बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्ताफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करें।' उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह फैसला आईपीएल 2026 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस पूरे मामले पर आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा, 'कोलकाता नाइट राइडर्स पुष्टि करता है कि बीसीसीआई और आईपीएल प्रबंधन ने आगामी आईपीएल सत्र से पहले मुस्ताफिजुर रहमान को टीम से रिलीज करने का निर्देश दिया है। यह फैसला बीसीसीआई के निर्देशों और सभी आवश्यक प्रक्रियाओं के तहत लिया गया है।

سال نامہ: رنگ بدلتی دنیا کا منظر نامہ

عابد انور

گزشتہ سال کی طرح یہ سال بھی زبردست اٹھل پھٹھل سے بھرا، جنگ و امن اور زبردست تبدیلیوں کا محور رہا۔ جہاں اس سال امریکی صدر ٹرمپ ایک میعاد کے وقفے کے بعد امریکہ کے سیاہ و سفید کے مالک بنے وہیں دو سال سے زائد جاری غزہ جنگ، جنگ بندی پر فتح ہوئی۔ گرچہ روس یوکرین جنگ جاری ہے لیکن امن منصوبے کی طرف معاملہ آگے بڑھ رہا ہے لیکن تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے باوجود جھڑپ جاری ہے۔ سوڈان اور ناہیر یا میں خانہ جنگی جاری ہے لیکن اس سال کے بڑے واقعات میں 12 سال سے جاری شام کی جنگ بند ہوگئی اور بعث پارٹی کے حکمران بشار الاسد کو ملک چھوڑ کر روس راہ فرار اختیار کرنا پڑی اور قطر کا کردار ایک مصالحت کار کے طور پر ابھر کر سامنے آیا۔

اکتوبر 2023 سے جاری غزہ اور اسرائیل جنگ امریکہ، قطر، مصر اور سعودی عرب کی ثالثی میں جنگ بندی پر ختم ہوگئی لیکن اس جنگ میں تقریباً 67 ہزار سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں جب کہ اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ ایک لاکھ سے زائد فلسطینی اس جنگ کی بھیبت چھ چکے ہیں، جن میں سے بہت سے فلسطینیوں کی لاشیں جلے میں دفن ہیں۔ زخمیوں کی تعداد ایک لاکھ سے زائد ہے۔ جدید دنیا کی سب سے سفاک جنگ جس میں اسرائیل نے تمام شیطانی رنگ دکھائے۔ اسرائیل نے اس وحشتناک جنگ میں عام شہریوں کو نشانہ بنایا، کم و بیش تمام ہسپتالوں پر بمباری کی گئی، اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ فلسطین اور غزہ میں انسان اور انسانیت کے جتنے ذرائع تھے انہیں امریکی اور یورپی ہتھیاروں سے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ زراعت کو اجاڑ دیا گیا۔ آبی وسائل کو نیست نابود کر دیا۔ غرضیکہ انسانی زندگی کے جتنے بھی وسائل ہو سکتے تھے انہیں اسرائیل نے تباہ و برباد کر دیا۔ اس جنگ کا سب سے انسانیت سوز پہلو یہ تھا اس میں بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ اس جنگ میں حماس کی اہلی قیادت کو قتل کر دیا گیا۔ اس جنگ اور فلسطینیوں کی قربانی کا مثبت پہلو یہ رہا تھا اس کے خلاف پوری دنیا میں آوازیں اٹھیں۔ اسرائیل سمیت، امریکہ، برطانیہ، جرمنی، اسٹریلیا، اسپین، روس، نیوزی لینڈ، کناڈا، چین، پاکستان، ایران اور چینممالک کو چھوڑ کر پوری دنیا میں اسرائیل کی جانب سے فلسطین میں نسل کشی کے خلاف زبردست آواز اٹھی۔ امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کے طلبہ نے ایسے احتجاج میں بھرپور حصہ لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے یونیورسٹی کے فنڈ روک لینے اور مختلف پابندیوں کے باوجود ہارورڈ یونیورسٹی سمیت دنیا کی بیشتر یونیورسٹیوں کے طلبہ نے اسرائیل کے خلاف احتجاج کیا۔ مختلف ممالک میں ہونے والے زبردست احتجاج اور عوامی دباؤ کے نتیجے میں امریکہ اور اسرائیل کی دھمکیوں کے باوجود دنیا کے بیشتر ممالک نے فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا۔

فلسطین میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملے جاری ہیں اور جنگ بندی کے بعد اب تک تقریباً ایک ہزار فلسطینی اسرائیلی حملے میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ امریکہ نے عندیہ دیا ہے کہ سال نو کے موقع پر جنگ بندی کا دوسرا مرحلہ شروع کیا جائے گا۔ اسرائیل غزہ جنگ کے دوران حماس کو بھاری قیمت چکانی پڑی اور اس کے ٹاپ کمانڈر اور

سربراہ بھی سنوار اسرائیلی حملے میں مارے گئے۔

اس سال دوسرا اہم واقعہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی بطور صدر حلف برداری ہے۔ حلف لیتے ہوئے انہوں نے پوری دنیا میں پھیل چلائی شروع کردی۔ فرسٹ امریکہ ایگن کے نعرے کے ساتھ انہوں نے مختلف ممالک پر دھونس جمائی شروع کیں اور اس کیلئے انہوں نے ٹریف کو اپنا اہم ہتھیار بنایا۔ دنیا کے بیشتر ممالک پر اپنی



منشاکے مطابق ٹریف لگانا شروع کر دیا۔ چین، کناڈا اور برازیل کے ساتھ تجارتی اختلافات بھی ہوئے۔ بالآخر ٹریف کی بات چیت کے بعد ان ممالک کے ساتھ تجارتی ٹریف کا مسئلہ حل کرنے میں ٹرمپ کامیاب رہے۔ اسی ٹریف کے ضمن میں ٹرمپ نے ہندوستان پر 50 فیصد ٹریف کا بوجھ ڈال دیا۔ انہوں نے روس سے ہندوستان کے تیل خریدنے پر اعتراض کیا اور تیل کی خریداری سے مکمل دستبرداری کا مطالبہ کیا اور پہلے 25 فیصد اور پھر 50 فیصد ٹریف عائد کر دیا۔ اسی کے ساتھ ٹرمپ نے سات ملکوں کے درمیان جنگ بند کرانے کا دعویٰ کیا جس میں ہندوستان اور پاکستان میں جنگ بندی بھی شامل ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے 40 بار سے زائد ہند پاک جنگ رکوانے کا دعویٰ کیا ہے اور اس کا اعادہ اب بھی جاری ہے۔ اسی طرح ٹرمپ گرین لینڈ کو امریکہ کا حصہ بنانے پر آمادہ نظر آئے۔ گرچہ انہوں نے کہا کہ معدنی وسائل کے لئے نہیں بلکہ امریکی قومی سلامتی کے لئے وہ امریکہ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ مزید براں وینزویلا کے ساتھ امریکہ کے شدید اختلافات ابھر کر سامنے آئے اور امریکہ نے منشیات کی اسمگلنگ کی روک تھام کے نام پر کئی حملے کئے جن میں تقریباً سو کے قریب لوگ مارے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ کئی مواقع پر امریکہ نے وینزویلا کے خلاف کارروائی کا اشارہ بھی دیا ہے۔

اس سال ایک اور اہم واقعہ میں ایران کے سابق صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے جاں بحق ہو گئے۔ اس ہیلی کاپٹر حادثے کے پس پشت سازش کی سوئی اسرائیل کی طرف گھومتی نظر آئی۔ اس کے بعد ہونے والے صدارتی انتخاب میں مسعود پڑھکیان صدر منتخب ہوئے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان 12 دن کی جنگ ہوئی جس

میں اسرائیل کا بہت سا حصہ کھنڈ نظر آیا اور اس جنگ میں ایران کے آرمی چیف اور پاسداران انقلاب کے سربراہ سمیت ایران کے ٹاپ جرنل مارے گئے۔ اس سے اسرائیل کے متعلق پوری دنیا کی غلط فہمی دور ہوگئی کہ اسرائیل ناقابلِ تسخیر ہے۔ ایران کی میزائلوں نے اسرائیل کے علاقے کو نشانہ بنایا خواہ فوجی تنصیبات ہوں یا نیکیائی مقامات لیکن اسرائیل کے آئرن ڈوم ایرانی میزائل کو روکنے



میں ناکام رہے۔ ایران پر حملے کے اخیر میں امریکہ بھی شامل ہوا اور امریکہ نے ایران کے متعدد نیکیائی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اس کے جواب میں ایران نے قطر میں واقع امریکی ایر بیس پر حملہ کیا۔

اس سال کے ایک اور اہم واقعے میں اسرائیل کے در دوسرے والے لیڈر اور لبنان میں حزب اللہ کے سکریٹری جنرل سید نصر اللہ اسرائیلی حملے میں جاں بحق ہو گئے۔ یہ حزب اللہ کے لئے ناقابلِ تلافی نقصان ثابت ہوا۔ جس کے بعد حزب اللہ کے اسرائیل پر حملے میں کمی واقع ہوگئی۔ اسی کے ساتھ لبنان میں ہجیر حملے میں درجنوں لبنانی عوام جاں بحق ہوئے یہ ہجیر حملہ اسرائیل نے کیا تھا۔ یمن کے حوثی نے بھی اسرائیل غزہ جنگ میں شامل ہوتے ہوئے اسرائیلی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور بحر احمر سے گزرنے والے امریکہ اور اسرائیل کے جہاز پر حملے شروع کر دیے۔ متعدد دھمکیوں اور امریکہ کے حملوں کے بعد بھی حوثیوں کے حملے جاری رہے اور بالآخر امریکہ کو حوثیوں کے ساتھ معاہدہ کر کے اپنی جان چھڑانی پڑی۔ اسرائیل نے حملہ کر کے یمن میں حوثی حکومت کے وزیر اعظم کو کاہینہ کے متعدد ارکان کے ساتھ مار ڈالا۔ یہ حوثیوں کے لئے بہت بڑا جھٹکا ثابت ہوا لیکن اس کے حوصلے میں کوئی کمی نہیں آئی۔

اسرائیل نے قطر کی ثالثی کے دوران دو وجہ میں حماس کے اہلکار پر حملہ کیا جس میں حماس کے اہلکار سمیت متعدد افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حملہ اسرائیل نے ایسے وقت میں کیا تھا جب جنگ بندی کے سلسلے میں مذاکرات آخری مرحلے تھے۔ جس کے لئے اسرائیل کو قطر سے معافی مانگی پڑی۔

آسٹریلیا کے ہونڈی بیچ پر یہودی تہوار کے موقع پر ایک دہشت

گردانہ حملے میں 16 افراد ہلاک ہو گئے اور 40 کے قریب زخمی ہوئے۔ اس حملے کا ملزم ساجد اکرم ہلاک اور دوسرا نوید اکرم زخمی ہو گیا اور اس پر عدالت میں چارج شیٹ داخل کر دی گئی۔ اس واقعہ میں الاحمد ہیرو بن کر ابھرے جو اپنی جان کی پروا کئے بغیر حملہ پر آور پرنوٹ پڑے اور ان سے ہتھیار چھین کر درجنوں لوگوں کی جانیں بچائیں۔ اس ہیرو کی دنیا میں بھر تعریف ہوئی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آسٹریلیا کے وزیر اعظم انٹونی البانیہز سمیت متعدد ممالک کے رہنماؤں نے ان کے جرات مندانہ قدم کو سراہا۔ آسٹریلیائی عوام نے اس ہیرو کی بہادری سے متاثر ہو کر لاکھوں ڈالر کے انعام سے نوازا۔

روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کی آنکھ بچوئی جاری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، روسی صدر ولادیمیر پوتن اور یوکرینی صدر ولودومیر زیلنسکی کے درمیان جنگ بندی اور مستقل قیام امن پر بات چیت جاری ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اس کی روپ ریکھا تیار کی ہے، جس میں زیلنسکی سے مشورہ نہیں لیا گیا اور ان کو یہ منصوبہ سپرد کر دیا گیا اور اس پر عمل درآمد کرنے کے لئے مختلف حربے اپنانے جارہے ہیں۔ زیلنسکی نے اپنی شرائط شامل کرنے کے لئے یورپی ممالک کا مسلسل دورہ کیا۔ 20 کانفی منصوبوں میں روسی مقبوضہ علاقہ سے یوکرینی دستبرداری سمیت یوکرین کی ناٹو میں شمولیت سے تو یہ بھی شامل ہے۔

اس سال کے اہم واقعات میں اپریل میں جموں و کشمیر کے معروف سیاحتی علاقہ پہلگام کی وادی بیسن میں سیاحوں پر حملہ بھی سے جس کے نتیجے میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ چھڑ گئی تھی دونوں نے ایک دوسرے پر ڈرون، میزائل اور طیاروں سے حملہ کیا تھا۔ ہندوستان نے اس آپریشن کا نام لائندور ✖ رکھا تھا جب کہ پاکستان نے اپنے آپریشن کا نام لبیان المروص ✖ رکھا تھا۔ اسی کے بارے میں ڈونالڈ ٹرمپ بار بار جنگ بندی کرانے کا دعویٰ کرتے رہے ہیں۔

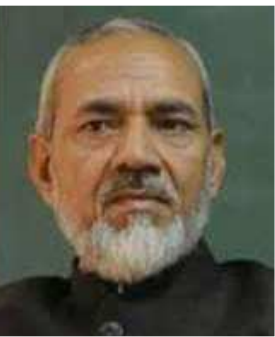
اس سال پیش آنے والے اہم واقعات میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جھڑپ بھی ہے جس میں دونوں طرف سیکورٹی فورسز ہلاک ہوئے تھے۔ اس کی وجہ سے پاک افغان سرحدیں بند رہیں جس کے سبب افغانستان میں اشیاء ضروریہ کا بحران پیدا ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ایران اور پاکستان سے لاکھوں افغان پناہ گزینوں کو جبراً افغانستان بھیج دیا گیا۔

عالمی طاقتوں، امریکہ، چین، روس، فرانس اور یورپ کے کئی ممالک کے درمیان سفارتی کشمکش جاری رہی۔ اسی کے ساتھ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان کاراباخ معاملے میں معاہدہ ہوا۔ بین الاقوامی واقعات میں صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا سعودی عرب کا دورہ بھی شامل ہے جس میں تقریباً 500 ارب ڈالر کا معاہدہ ہوا۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے ساتھ قطر اور متحدہ عرب امارات کا بھی دورہ کیا تھا۔ اس دورے کے دوران صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کے علاوہ قطر اور متحدہ عرب امارات سے اربوں ڈالر کا معاہدہ کیا تھا۔ اس سال کے اہم واقعات میں فلپائن، ہندوستانی پنجاب اور پاکستانی پنجاب اور پنجاب کے دیگر علاقوں میں تباہ کن سیلاب بھی ہے اس کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی سیلاب کی تباہ کاریاں جاری رہیں۔ جس کی وجہ سے جان و مان کا زبردست نقصان ہوا۔

قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی جلد از جلد تشکیل کیلئے اردو نے وزیر اعظم کو مکتوب لکھا

این سی پی یو ایل کی باڈی تشکیل دی جائے تاکہ انتظامی ڈھانچہ پوری طرح فعال ہو سکے اور اردو زبان کے فروغ کے لیے جاری کاموں کو تیزی اور موثر طریقے سے آگے بڑھایا جاسکے: ڈاکٹر سید احمد خاں

پی یو ایل (کا قیام کیا گیا ہے اور وزارت تعلیم کے تحت یہ کام کرتا ہے لیکن یہ تشویشناک بات ہے کہ گزشتہ تین سالوں سے نہ تو اس چیئر مین کی تقرری ہوئی ہے اور نہ ہی اس کی تشکیل اب تک ہو پائی ہے جس کے سبب کونسل پوری طرح سے کام نہیں کر پا رہا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ این سی پی یو ایل کی باڈی تشکیل دی جائے تاکہ انتظامی ڈھانچہ پوری طرح فعال ہو سکے اور اردو زبان کے فروغ کے لیے جاری کاموں کو تیزی اور موثر طریقے سے آگے بڑھایا جاسکے۔ ڈاکٹر سید احمد خاں نے وزیر اعظم سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ قومی کونسل برائے فروغ اردو کی جلد از جلد تشکیل کی طرف توجہ دی جائے تاکہ وسیع تر مفاد میں اس کی سرگرمیاں جلد از جلد دوبارہ شروع ہو سکیں۔ ہم آپ کے مشکور ہوں گے۔



زبان کو فروغ ملا ہے۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ اس کی مقبولیت میں بے حد اضافہ ہوا ہے اور آج بھی ہر کس و ناکس کی پسندیدہ زبان اردو ہے۔ اس زبان کو ہر دور میں نصر ف سرکاری بلکہ عوامی سطح پر محبت اور ثقافت کی زبان کے طور پر قبول کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اردو زبان کی ترقی و ترویج کیلئے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان (این سی پی یو ایل)

نئی دہلی: اردو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی باڈی کی جلد از جلد تشکیل کیلئے وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھا ہے۔ اس تعلق سے بات کرتے ہوئے اردو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے قومی صدر ڈاکٹر سید احمد خاں نے کہا کہ کونسل کی تشکیل میں تاخیر سے اردو زبان کی ترقی اور فروغ کے کام متاثر ہو رہے ہیں۔ سکول کا بنیادی مقصد قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان (این سی پی یو ایل) کی کارکردگی کو بہتر بنانا اور اردو زبان کے فروغ کے منصوبوں کو تیزی سے آگے بڑھانا ہے۔ یہ کام اچھے ڈھنگ سے سمجھے ہو سکتے ہیں جب اس کی تشکیل عمل میں آئے گی۔ اردو زبان کی اہمیت و افادیت پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر سید احمد خاں نے کہا کہ اردو کی پیدائش بھارت میں ہی ہوئی ہے اور یہی اس

دنیا سال بھر جنگ ہتازات، حکومت کی تبدیلی، بغاوتوں اور عدم استحکام سے دوچار رہی

نیرج کمار دوہے

سے کہیں زیادہ جارحانہ، قوم پرست اور تصادم کا شکار نظر آیا۔ اس کی پالیسیوں نے عالمی تجارت، سیکورٹی اتحاد اور سفارتی توازن کو متاثر کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ امریکی خارجہ پالیسی امریکہ فرسٹ کے نقطہ نظر کی طرف لوٹ رہی ہے، جس کی وجہ سے یورپ سے ایشیا تک اتحادیوں میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ ٹرمپ کے انداز نے اتحادیوں کو بھی یہ سوال کرنے پر مجبور کیا کہ آیا امریکہ اب بھی قابلِ اعتماد پارٹنر ہے۔ مزید برآں، 2025 میں کئی ممالک میں نئی حکومتوں کا قیام عمل میں آیا۔ کچھ ممالک میں، یہ منتقلی جمہوری عمل کا نتیجہ تھی، جب کہ کچھ ممالک میں، یہ سیاسی عدم استحکام کا نتیجہ تھا۔ انتخابات نے افریقہ، یورپ اور بحر الکاہل کے کئی چھوٹے اور بڑے ممالک میں نئی قیادت کو سامنے لایا۔ اقتدار کی ان تبدیلیوں نے یہ ظاہر کیا کہ جمہوریت ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی، لیکن یہ بھی واضح

سال 2025 عالمی سیاست کی تاریخ میں ایک ایسے سال کے طور پر گرا جس نے یہ واضح کر دیا کہ دنیا اب استحکام کی طرف نہیں بلکہ تیزی سے عدم استحکام، تنازعات اور اقتدار کی کشمکش کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس سال نے جمہوریت اور آمریت، امن اور جنگ، مذاکرات اور تصادم کے درمیان خطوط کو مزید دھندلا کر دیا۔ کچھ جگہوں پر انتخابات کے ذریعے حکومتیں تبدیل ہوئیں، کچھ جگہوں پر بندھنوں کے زور سے اقتدار پر قبضہ کر لیا گیا، جب کہ کچھ جگہوں پر جنگ اور محدود تنازعات نے ایک بار پھر انسانیت کو آزمائش میں ڈال دیا۔ سال 2025 ایک بڑے جھٹکے کے ساتھ شروع ہوا جب ڈونلڈ ٹرمپ نے ریاستہائے متحدہ کے صدر کا عہدہ سنبھالا۔ ان کی واپسی صرف امریکہ تک محدود نہیں رہی بلکہ اس کا اثر پوری دنیا میں محسوس کیا گیا۔ ٹرمپ کا دوسرا دور پہلے

Yellow Alert

Light Rain Likely in Delhi on New Year's Day; Yellow Alert for Fog Issued

New Delhi: Weather conditions have changed across Delhi and the National Capital Region (NCR). The national capital is currently covered in a blanket of fog, with dense cloud cover prevailing in many areas.

According to the India Meteorological Department (IMD), light rain or drizzle is likely in Delhi and several parts of the NCR on New Year's Day. The weather is expected to remain unsettled even after the rainfall.

On January 1, Delhi is likely to remain cloudy throughout the day,



with light to moderate fog during the morning hours. Light rain or drizzle may occur in different parts of Delhi and the NCR.

On January 2, the sky is expected to remain partly cloudy. Light fog is likely in many areas during the morning, while dense fog may occur at some places. The IMD has issued a yellow alert for fog for January 2. A similar yellow alert for fog has also been issued for January 3, with light to dense fog expected in several

parts of Delhi and the NCR during the morning hours.

From January 4 to January 5, the sky is expected to remain clear, although light to moderate fog may persist in the mornings.

The minimum temperature in Delhi on January 1 and 2 is expected to range between 9°C and 11°C. A drop in temperature is likely thereafter, with minimum temperatures between 7°C and 9°C expected on January 3, 5, and 6. Weather conditions in NCR cities are expected to remain largely similar.

Delhi Police Seize Heroin Worth Over 10 Crore

New Delhi: Delhi Police's Crime Branch has busted a drug supply network allegedly planning to distribute narcotics during New Year celebrations. During a raid, police seized 2.034 kilograms of heroin, estimated to be worth over Rs. 10 crore, and arrested two suspected members of a professional drug trafficking syndicate.

The arrested accused have been identified as Anshul Rana and Ganga Prasad alias Vicky, who are believed to be key members of a regional drug syndicate. Police also seized six mobile phones, which were allegedly being used to coordinate cross-border operations, and impounded the vehicle used for supplying heroin across the Delhi-NCR region.

During interrogation, Anshul Rana



reportedly confessed that he was part of an organised gang involved in heroin distribution in Delhi-NCR. He disclosed that the seized consignment had been procured from Ganga Prasad alias Vicky, who sourced the heroin from Bareilly in Uttar Pradesh.

Earlier this month, the Delhi Police Anti-Narcotics Task Force busted an inter-state drug racket and seized 348.176 kilograms of ganja, valued at approximately Rs. 1.75 crore in the international market. The contraband was being transported from Andhra Pradesh to Delhi-NCR, concealed in a truck carrying watermel-

ons. Two accused, Intezaar Malik and Rizwan, were arrested in that case.

Meanwhile, the South-East District of Delhi Police conducted a special drive named 'Operation Aaghat 3.0' on Friday. Under the operation, 285 accused were arrested under the Excise Act, NDPS Act and Gambling Act. As a preventive measure, 504 individuals were detained, while 116 listed offenders were also arrested. During the operation, police recovered 21 country-made pistols, 20 live cartridges and 27 knives.

Additionally, 12,258 quarters of illicit liquor, 6.01 kilograms of ganja, and ₹2.30 lakh in cash were seized. Police also confiscated 310 mobile phones, 231 two-wheelers, and one four-wheeler.

Two arrested in Faridabad gang-rape case

Faridabad: Two accused have been arrested on the charges of gang-raping a woman in a moving van for two hours in Haryana's Faridabad after offering her a lift, police said on Wednesday.

According to the officials, the incident occurred on the intervening night of Monday and Tuesday.

A woman was trying to find a ride home when a van stopped, and two men lured her into the vehicle. They promised her that they would get her home, but instead took a turn towards the Gurgaon Road.

When the woman objected, she was beaten. The accused raped her for two hours and later threw her out of the moving car near SGM Nagar and fled the scene. The woman was admitted to a private hospital in an injured



condition.

An FIR has been registered based on the complaint of the victim's family, and the police are checking CCTV camera footage.

Police spokesperson Yashpal Singh said that the victim's sister stated in her complaint that she received a call from her sister at 8.30 p.m., who told her that she had an argument with her mother at home and was going to her friend's house.

The victim said she would return from her friend's house in three hours.

According to the victim's sister,

around 12.00 a.m., the victim was waiting for a ride to go home, but failed to get it. Soon after, the accused offered a lift to the victim, which she accepted.

It is alleged that after giving her a lift, the two men drove the van towards Gurugram Road. After passing the Hanuman Temple on the Faridabad-Gurugram road, one of the accused continued driving the car while the other raped the woman. The accused drove around on the Faridabad-Gurugram road for two hours, according to the officials.

جماعتِ اسلامی ہند، دہلی حلقہ کا دوروزہ تربیتی کیمپ کامیابی کے ساتھ منعقد

استقامت، اخلاص اور مسلسل جدوجہد ہی کامیابی کا راستہ ہے: امیرِ حلقہ



پیش کیے۔ اس موضوع پر اختتامی خطاب ڈاکٹر شفیق احمد صلاحی نے کیا۔ تیسرا موضوع تزکیہ تھا، جس میں ڈاکٹر وقار نور نے شرکاء کو اللہ کی راہ میں اپنی صلاحیتوں کو بچانے اور بروئے کار لانے کی ترغیب دی۔ اس نشست میں ڈاکٹر خان یاسر کی رہنمائی میں ایک عملی ورکشاپ بھی منعقد ہوئی، جس میں شرکاء نے مرحلہ وار اپنا ذاتی تربیتی منصوبہ تیار کیا۔ کیمپ کا چوتھا موضوع تنظیمی شعور

نئی دہلی (پریس ریلیز) جماعتِ اسلامی ہند، دہلی حلقہ کے زیرِ اہتمام دوروزہ تربیتی کیمپ ”نئی دہلی میں منعقد ہوا۔ کیمپ میں تقریباً 75 منتخب رفقاء نے شرکت کی۔ یہ تربیتی کیمپ چار موضوعاتی نشستوں پر مشتمل تھا۔ کیمپ کا پہلا موضوع افراد سازی تھا، جس کے تحت جناب محمد احمد اور جناب انعام اللہ فلاحی نے اصلاحی و حوصلہ افزا خطابات کیے۔ بعد ازاں ڈاکٹر خان یاسر نے اس موضوع کے عملی پہلوؤں پر ایک ورکشاپ کرائی، جبکہ اجلاس کی صدارت جناب شفیق مدنی نے کی۔ کیمپ کا دوسرا موضوع مطالعہ تھا۔ اس نشست میں مولانا صدر الدین اصلاحی کی کتاب ”مسلمان اور دعوتِ اسلام“ پر اجتماعی مطالعہ اور گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد جناب جاوید اقبال نے مطالعہ کے صحیح طریقوں پر خطاب کیا۔ شرکاء نے اسلام اور جاہلیت، اسلام کا نظام حیات، تحریک اور کارکن اور تحریکی شعور جیسی کتب پر تبصرے

سائنس اور ٹیکنالوجی کا امتزاج معاشی و سماجی ترقی کا ضامن: پروفیسر اے تیجا

خواجہ یونیورسٹی میں سائنس ماڈل مقابلہ اور یک روزہ سیمینار کا انعقاد



کہا کہ بین العلوم ہم آہنگی موجودہ عہد کی سب سے بڑی ضرورت ہے کیونکہ عصری مسائل صرف ایک علم کی مدد سے حل نہیں کیے جاسکتے۔ انھوں نے کہا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا امتزاج نہ صرف معاشی و سماجی ترقی کا ذریعہ ہے بلکہ یہ انسانی زندگی کو بہل اور بہتر بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پروفیسر اے تیجا نے طلبہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ تحقیق اور اختراع کو محض نصابی سرگرمی تک محدود نہ رکھیں بلکہ اسے عملی زندگی کے مسائل کے حل سے جوڑیں۔ انھوں نے اس طرح کے سیمینارز اور سائنس ماڈل مقابلوں کو نوجوان نسل کے اندر تحقیق، اختراع اور قائدانہ صلاحیتوں کو ابھارنے کا مؤثر ذریعہ قرار دیا اور یونیورسٹی

کھنؤ (پریس ریلیز) خواجہ معین الدین چشتی لینگوتج یونیورسٹی میں آج کیمپری سطح سائنس ماڈل مقابلہ اور ایک روزہ سیمینار سائنس و ٹیکنالوجی میں بین العلوم ہم آہنگی اور جدید پیش رفت کے عنوان سے منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام کا مقصد طلبہ میں سائنسی شعور، تحقیقی فکر اور تحقیقی صلاحیتوں کو فروغ دینا تھا۔ افتتاحی اجلاس میں استقبالیہ کلمات پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر اچھے کرشنا نے مہمانوں، ماہرین تعلیم اور شرکاء کا خیر مقدم کیا۔ انھوں نے سیمینار کی اہمیت اور معنویت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ایسے علمی و سائنسی پروگرام طلبہ میں سائنسی سوچ، تحقیقی صلاحیت اور تحقیقی رجحان کو مضبوط بنانے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ انھوں نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ دور میں سائنس کسی ایک شعبے تک محدود نہیں رہی بلکہ مختلف علوم کے باہمی اشتراک اور ہم آہنگی ہی کی سے نئی ایجادات اور مؤثر حل سامنے آ رہے ہیں۔ اس تناظر میں طلبہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو جامع اور کشیدہ جہتی نقطہ نظر سے سمجھیں۔ سیمینار کے افتتاحی اجلاس کی صدارت وائس چانسلر پروفیسر اے تیجا نے کی۔ اپنی صدارتی تقریر میں انھوں نے

خواجہ معین الدین چشتی لینگوتج یونیورسٹی میں یوجی، پی جی اور ڈپلومہ کے تمام نتائج جاری



حاصل کردہ نمبروں میں کسی بھی قسم کی غلطی پائی جائے یا امتحانی نتیجے سے متعلق کوئی اور مسئلہ درپیش ہو تو وہ 6 جنوری 2026 تک انتظامی عمارت میں واقع شعبہ امتحانات سے رابطہ کر کے اپنی شکایت درج کر سکتے ہیں۔ امتحانات کنٹرولر کے مطابق تمام شعبہ جات کے سربراہان اور اساتذہ کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے شعبوں کے طلبہ کو اس اطلاع سے بروقت آگاہ کریں، تاکہ کسی طالب علم کو نتیجہ دیکھنے یا اعتراض درج کرانے میں دشواری نہ ہو۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی کے آئی ٹی شعبہ کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ نتائج کو ویب سائٹ پر نمایاں طور پر شائع رکھا جائے۔

یونیورسٹی گیمز کمیٹی، اے ایم یو میں مختلف کلبوں کے صدور کا تقرر علی گڑھ (پریس ریلیز) علی گڑھ مسلم یونیورسٹی وائس چانسلر نے یونیورسٹی گیمز کمیٹی کے سکریٹری کی سفارش پر مختلف کلبوں کے صدور مقرر کئے ہیں۔ شعبہ کمارس کے پروفیسر محمد شمیم بانکنگ اینڈ ماؤنٹینرنگ کلب کا صدر مقرر کیا گیا ہے۔ یونیورسٹی پولی ٹینک کے الیکٹرککل انجینئرنگ سیکشن سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر محمد سرفراز عالم کو رائیڈنگ کلب کا صدر نامزد کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر یاسر اعظم (شعبہ پلاننگ مینسٹری) ٹینس کلب کے صدر ہوں گے، جبکہ شعبہ فزیکل ایجوکیشن کے ڈاکٹر معراج الدین فریدی کو ایتھلیٹکس کلب کا صدر مقرر کیا گیا ہے۔

اے ایم یو کے جوئیئر ریز یڈنٹ نے قومی کانفرنس میں پہلا انعام حاصل کیا

علی گڑھ (پریس ریلیز) جواہر لعل نہرو میڈیکل کالج (اے این ایم سی)، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی (اے ایم یو) کے شعبہ کمیونٹی میڈیسن میں سال آخر کے جوئیئر ریز یڈنٹ ڈاکٹر محمد بلال نے اجمال خاں طبیہ کالج کے شعبہ معالجات کے زیر اہتمام منعقدہ قومی کانفرنس میں پوسٹر پرنٹیشن کے زمرے میں پہلا انعام حاصل کیا۔ ڈاکٹر بلال کو ان کے پوسٹر بعنوان ”غذائی فائبر بطور پریوینٹو میڈیسن“ کے لئے یہ اعزاز ملا۔ یہ پوسٹر، شعبہ کمیونٹی میڈیسن کے ڈاکٹر علی جعفر عابدی کی نگرانی میں تیار کیا گیا، جس میں خصوصاً عوامی صحت میں غذائی فائبر خاص طور سے ایسٹروفل کے حفاظتی کردار کو اجاگر کیا گیا۔ اس مطالعے میں یونانی طب کے قدیم تصورات کو جدید نیوٹراسیوٹک تحقیق کے معاصر شواہد کے ساتھ ہم آہنگ کیا گیا۔ شعبہ کمیونٹی میڈیسن کی چیئر پرسن پروفیسر عطیٰ ارم نے اس کامیابی پر ڈاکٹر محمد بلال کو مبارکباد پیش کی۔

اے ایم یو الومنی ایسوسی ایشن، قطر نے داستان گوئی کی تقریب کا انعقاد

علی گڑھ (پریس ریلیز) علی گڑھ مسلم یونیورسٹی الومنی ایسوسی ایشن قطر نے کانجانی ہال، انڈین کچنل اینڈ بزنس فورم، دوحہ میں ایک شاندار ثقافتی شام کا اہتمام کیا، جس میں مہاجرین کے تجربات پر مبنی داستان گوئی پیش کی گئی۔ معروف بین الاقوامی ٹیڈ آرٹسٹ، شاعر اور مصنف جاوید دانش نے اپنی مشہور انفرادی پرفارمنس ”داستان ہجرتوں کی“ پیش کی، جو مہاجرین کے جذباتی اور سماجی سفر کی طاقتور داستان ہے۔ اس داستان گوئی نے تقریباً ایک گھنٹہ تک حاضرین کو محظوظ اور مسحور رکھا، اور ترک وطن، تعلق، یاد اور صبر و استقامت کے موضوعات پر غور و فکر کی دعوت دی۔ پھر سے ہونے والے حاضرین نے کھڑے ہو کر اس پیشکش کو سراہا۔ ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر ندیم جیلانی نے حاضرین کا خیر مقدم کرتے ہوئے ایسوسی ایشن کی ثقافتی اور ادبی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا، جب کہ ڈاکٹر آشنا نصرت، نائب صدر (لیڈیز ونگ) نے ایسوسی ایشن کے مختلف اقدامات کا خاکہ پیش کیا۔ چیئر مین انجینئر جاوید احمد اور ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین نے جاوید دانش کو یادگاری نشان اور راقی شال پیش کی اور انہیں اے ایم یو کے ممتاز سابق طالب علم کے طور پر خراج تحسین پیش کیا۔ کنڈا میں منہج جاوید دانش، رنگ منچ، کنڈا کے آرٹسٹک ڈائریکٹر ہیں اور شاہی امریکہ میں داستان گو کے طور پر معروف ہیں۔ وہ ہیں سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں، اور ان کا سولو ڈرامہ ”مائی سن از آرٹسٹک“ کا اٹھیں زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس موقع پر، جاوید دانش کی مرتب کردہ کتاب ”پس دسٹرس“ کا اجراء بھی عمل میں آیا جو احمد اشفاق کی شاعری پر تنقیدی تحریروں پر مبنی ہے۔ الومنی ایسوسی ایشن نے اپنے پہلی سالانہ میگزین ”ابر علی گڑھ“ بھی انھیں پیش کی۔ آخر میں ایسوسی ایشن کے نائب صدر ارشد محمد فیصل نسیم نے اظہار تشکر کیا۔

اے ایم یو میں شعبہ بزنس ایڈمنسٹریشن کے سابق طلبہ (نچ 2000) کی ری یونین تقریب منعقد

علی گڑھ (پریس ریلیز) علی گڑھ مسلم یونیورسٹی (اے ایم یو) کے شعبہ بزنس ایڈمنسٹریشن، فیکلٹی آف مینجمنٹ اسٹڈیز اینڈ ریسرچ کے 2000 نچ کے طلبہ نے اپنی فراغت کے پچیس برس مکمل ہونے کے موقع پر ایک خصوصی تقریب بازگشت: اے ہوم کمنگ کے عنوان سے منعقد کی جس میں سابق طلبہ، سینئر اساتذہ اور یونیورسٹی انتظامیہ کے اراکین نے شرکت کی اور قدیم یادوں کو تازہ کرتے ہوئے ادارے سے مضبوط و دیرپا تعلقات کی تجدید کی۔ تقریب سے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے اے ایم یو وائس چانسلر پروفیسر نعیمہ خاتون نے یونیورسٹی کی ترقی و فروغ میں سابق طلبہ کے کردار کی اہمیت پر زور دیا۔ انھوں نے کہا کہ سابق طلبہ کی فعال شمولیت تعلیمی ماحول کو بہتر بناتی ہے، ادارے کی سادھ میں اضافہ کرتی ہے اور طلبہ کی ہمہ جہت ترقی میں نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ انھوں نے سابق طلبہ سے کہا کہ وہ اپنی مادر علمی سے قریبی رابطہ برقرار رکھیں اور رہنمائی، سرپرستی اور ادارہ جاتی تعاون کے ذریعے اپنا کردار ادا کریں۔ فیکلٹی آف مینجمنٹ اسٹڈیز اینڈ ریسرچ کے ڈین پروفیسر محمد نوید خان نے یونیورسٹی کے تعلیمی اور پیشہ ورانہ مقام کو بلند کرنے میں سابق طلبہ کے کلیدی کردار کو اجاگر کیا۔ انھوں نے بتایا کہ نچ 2000 کے کئی افراد ملک و بیرون ملک اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، جس سے اے ایم یو کی عالمی شناخت کو تقویت ملتی ہے۔ سابق طلبہ کا خیر مقدم کرتے ہوئے صدر شعبہ پروفیسر سلمیٰ احمد نے کہا کہ تقریباً پچیس برس قبل 2000 نچ کے طلبہ نے اے ایم یو میں ایم بی اے میں اپنے تعلیمی سفر کا آغاز کیا تھا اور آج بھی اپنے اپنے شعبوں میں نمایاں مقام پر فائز ہیں۔ سابق فیکلٹی رکن پروفیسر جاوید اختر نے بھی خطاب کیا اور نچ 2000 کی میراث اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی قائم کردہ پائیدار تعلیمی اقدار پر روشنی ڈالی۔ پروفیسر پرویز طالب نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ شعبہ اپنے سابق طلبہ کو ہمیشہ خوش آمدید کہتا رہے گا تاکہ باہمی ادارہ جاتی تعلقات کو فروغ دیا جاسکے۔ اس موقع پر متعدد سابق طلبہ نے اپنے تجربات بیان کئے۔

کھنؤ (پریس ریلیز) خواجہ معین الدین چشتی لینگوتج یونیورسٹی نے تعلیمی سیشن 2024-25 کے تحت انڈر گریجویٹ (یوجی)، پوسٹ گریجویٹ (پی جی) اور ڈپلومہ کورسز کے تمام مسٹرز کے امتحانی نتائج جاری کر دیے ہیں۔ یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے جاری باضابطہ اطلاع کے مطابق پہلے، تیسرے، پانچویں اور ساتویں سمسٹر کے تمام امتحانات کے نتائج یونیورسٹی کی سرکاری ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیے گئے ہیں۔ اطلاع میں بتایا گیا ہے کہ تمام متعلقہ طلبہ و طالبات اپنے امتحانی نتائج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ پورٹل پر لاگ ان آئی ڈی کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ طلبہ اپنی آن لائن مارک شیٹ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جسے عارضی طور پر تعلیمی اور دیگر ضروری امور کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ اگر کسی طالب علم کے نام، والد یا والدہ کے نام، رول نمبر یا

केंद्र सरकार ने इस वर्ष 1 लाख 51 हजार 282 करोड़ रुपये आवंटित किए

जी राम जी एक्ट भ्रष्टाचार मुक्त ग्रामीण रोजगार की गारंटी- नायब सिंह सैनी



चंडीगढ़ - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विकसित भारत - रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) कानून, 2025 भ्रष्टाचार मुक्त ग्रामीण रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। यह ग्रामीण रोजगार नीति अधिक गारंटी वाले कार्यदिवस, उच्च मजदूरी, पारदर्शी भुगतान और टिकाऊ संपत्तियों के निर्माण को सुनिश्चित करता है। इस नए कानून से पहले की मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार और खामियों को दूर किया गया है।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों के कल्याण और गांवों के विकास में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत-जी राम जी योजना शुरू की है। यह विषय देश के करोड़ों ग्रामीण श्रमिकों, किसानों और मेहनतकश परिवारों से जुड़ा हुआ है।

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, श्री रणबीर गंगवा, श्री कृष्ण कुमार बेदी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर और मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय भी उपस्थित रहे।

उन्होंने कहा कि वीबी जी-राम जी कानून का उद्देश्य उन वास्तविक श्रमिक लाभार्थियों का समर्थन करना है, जिन्हें पिछली सरकारों ने धोखा दिया था। यह अधिनियम परियोजनाओं की वास्तविक समय में निगरानी की व्यवस्था करता है, मजदूरी भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। श्रमिकों को गारंटीकृत रोजगार बढ़ाकर अधिक मजदूरी देती है। ये श्रमिक अब भ्रष्ट ठेकेदारों, अधिकारियों या राजनेताओं की तिजोरियाँ भरने के लिए नहीं, बल्कि विकसित भारत के निर्माण की दिशा में काम करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा योजना लगभग

छ वर्ष पहले शुरू की गई थी। मनरेगा और ऐसी ही अन्य कई योजनाओं की प्रकृति ही ऐसी होती है कि इन्हें तैयार किया जाता है, पारित किया जाता है, लागू किया जाता है और इनमें सुधार भी किया जाता है। मनरेगा के अंतर्गत कई समस्याएं सामने आईं, जैसे कि श्रमिकों के बजाय मशीनों का उपयोग करना, बजट का अत्यधिक अनुमान, पहले से पूर्ण की गई परियोजनाओं को दोबारा करना, और ऐसी ही कई कमियां देखने को मिलीं, लेकिन आज सच्चाई यह है कि देश, समाज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पिछले 20 वर्षों में मूल रूप से बदल चुके हैं। ग्रामीण गरीबी वर्ष 2011-12 में जहां 25 प्रतिशत से अधिक थी, वहीं आज यह घटकर लगभग 5 प्रतिशत से भी नीचे आ चुकी है। इसका अर्थ है कि वर्तमान केंद्र सरकार की सकारात्मक नीतियों के कारण 25 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं।

उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डिजिटल कनेक्टिविटी, बैंकिंग सेवाओं, डी.बी.टी., आधार और बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। ऐसे में एक पुराने, खामियों से भरे ढांचे को बिना सुधार के ढोते रहना न तो श्रमिकों के हित में था और न ही राष्ट्र के।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नए प्रावधानों के तहत, रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करने से श्रमिकों की गारंटीशुदा मजदूरी को काफी बढ़ावा मिला है। इसके माध्यम से, सरकार श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास कर रही है। इससे पूरे भारत वर्ष में एक ग्रामीण अकुशल श्रमिक की वार्षिक आय में औसतन 7 हजार रुपये से अधिक की बढ़ोतरी होगी। हरियाणा में मजदूरी दर ज्यादा है, इसलिए हर श्रमिक को कम से कम 6 हजार रुपये अधिक मिलेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई योजना से न केवल काम के अधिक दिन सुनिश्चित होंगे, जिससे बेहतर वेतन मिलेगा, बल्कि अनिवार्य साप्ताहिक वेतन भुगतान (अधिकतम 15 दिनों तक की देरी की अनुमति के साथ) से श्रमिकों को समय पर बढ़ा हुआ वेतन प्राप्त होगा। इससे आर्थिक स्वतंत्रता और सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा। इसे संभव बनाने के लिए, केंद्र सरकार ने इस वर्ष 1 लाख 51 हजार 282 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जबकि पिछले वर्ष यह राशि 88 हजार करोड़ थी, जो उस समय तक का सबसे अधिक आवंटन था यानी पिछले रिकॉर्ड आवंटन को भी पार कर लिया गया है। इसमें अकेले केंद्र सरकार का हिस्सा 95 हजार करोड़ रुपये से अधिक होगा, जिसे सरकार आने वाले वर्षों में बढ़ाने का वादा करती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत इस वर्ष हरियाणा में 52 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति के श्रमिकों को तथा 65 प्रतिशत से अधिक महिला श्रमिकों को काम मिला है। यह काम वास्तव में उन्हें मिला है। पहले तो मशीनों से काम करवा लिया जाता था और उन्हें वास्तव में काम मिलता ही नहीं था।

उन्होंने कहा कि इस कानून में कार्यों की प्रकृति को भी बदला गया है। पहले मनरेगा के तहत सीमित रोजगार दिया जाता था। अब जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संसाधन और जलवायु परिवर्तन से निपटने वाली स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण में भी रोजगार दिया जाएगा। ग्राम पंचायतों की योजनाओं को पी.एम. गति शक्ति मास्टर प्लान से जोड़ा गया है, ताकि गांवों में होने वाला हर काम राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप हो।

उन्होंने कहा कि इस योजना में अब कृषि के चरम मौसम के दौरान 60 दिनों का विराम शामिल किया गया है ताकि देश के किसान और

मजदूर मिलकर काम कर सकें और मजदूरों को कृषि मौसम के दौरान उनके श्रम के लिए बाजार की उच्च दरें मिल सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार से निपटने, शोषण को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल वास्तविक श्रमिकों को ही पारदर्शिता के साथ उनका हक मिले, वीबी जी- राम जी योजना में कई उपाय किए गए हैं। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और उपस्थिति से फर्जी कर्मचारियों, डुप्लिकेट जॉब कार्ड और फर्जी भुगतानों को रोका जा सकेगा। वेतन और भत्तों का सीधा, डिजिटल भुगतान इससे बिचौलियों, वेतन भुगतान में देरी और धन के दुरुपयोग की समस्या समाप्त हो जाएगी। जियो-टैगिंग और सैटेलाइट इमेजरी इस योजना के तहत बनाई गई प्रत्येक संपत्ति को जियो-टैग किया जाएगा और इसरो के भुवन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि भ्रष्ट ठेकेदारों या अधिकारियों द्वारा फर्जी परियोजनाओं का पंजीकरण न हो सके। साप्ताहिक सार्वजनिक खुलासे इससे श्रमिकों की सूची, भुगतान, प्रतिबंध और निरीक्षण सार्वजनिक रूप से दिखाई देते हैं। शिकायत रजिस्टर और ब्लॉक एवं जिला स्तर पर बहुस्तरीय शिकायत निवारण के साथ दिवसीय निपटान समय सीमा अंतहीन विवादों और मुकदमों के बजाय अनियमितताओं पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करता है, साथ ही पूर्वाग्रह और दमन को समाप्त करता है।

उन्होंने कहा कि धन की हेराफेरी के लिए धोखे से बनाई गई फर्जी परियोजनाओं को रोकने के लिए, नए प्रावधानों को चार क्षेत्रों में बांटा जाएगा। जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संसाधन और जलवायु संरक्षण। अब, यह योजना भ्रष्टाचार का अड्डा बनने के बजाय विकास में एक वास्तविक और ठोस योगदानकर्ता के रूप में काम करेगी।

ادھم پور میں مشن یووا کے تحت انٹر پرائیور شپ اور بیداری میلے کا انعقاد

ادھم پور (ایجنسیاں) ڈسٹرکٹ ایگسٹائمنٹ اینڈ کونسلنگ سینٹر نے حال ہی میں مشن یووا کے تحت خواتین اور سیلف ہیلمپ گروپس میں خود روزگاری اور کاروباری جذبے کو فروغ دینے کے لیے ایک روزہ انٹر پرائیور شپ کم بیداری میلے کا انعقاد کیا۔ ادھم پور ضلعی انتظامیہ کے تعاون سے منعقد کی گئی اس پہل کا مقصد مقامی خواتین کو حکومت کے زیر اہتمام مختلف کاروباری ترقی کے پروگراموں کے ذریعے خود روزگار کے مواقع تلاش کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے آگاہ کرنا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ تقریب کا باقاعدہ افتتاح ایڈیشنل ضلع ترقیاتی کمشنر و دو کمآر اند اور دیگر افسران نے کیا۔

نئی دہلی (پریس ریلیز) دہلی کے سرکاری اسکولوں کے اساتذہ کو آوارہ کتوں کی گنتی اور ان کی نگرانی کا حکم جاری کر کے بی جے پی حکومت عام آدمی پارٹی کے نشانے پر آگئی ہے۔ اس حکم کے جاری ہوتے ہی عام آدمی پارٹی کی دہلی ریاستی کانٹی کے رہنما بی جے پی حکومت پر حملہ آور ہیں اور اب پارٹی کے قومی کنوینر اور دہلی کے سابق وزیر اعلیٰ اروند کچر یووال نے بھی اس فیصلے پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ منگل کے روز اروند کچر یووال نے بی جے پی حکومت سے سوال کیا کہ دہلی میں سرکاری اسکولوں کے اساتذہ بچوں کو پڑھائیں گے یا سڑکوں پر آوارہ کتوں کی گنتی کریں گے؟ بی جے پی حکومت کے اس حکم نے تعلیم کے تئیں اس کی سوچ اور ترجیحات کو پوری طرح بے نقاب کر دیا ہے۔ عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اور دہلی کے سابق وزیر اعلیٰ اروند کچر یووال نے ایکس پر کہا کہ دہلی میں سرکاری اسکولوں کے

اساتذہ بچوں کو پڑھائیں گے یا پھر سڑکوں پر کتوں کی گنتی کریں گے؟ بی جے پی کی دہلی حکومت کا یہ حکم اس کی سوچ اور ترجیحات کو بے نقاب کرتا ہے۔ بی جے پی کے لیے تعلیم کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ اساتذہ کی توجہ کر رہے ہیں اور اسکولوں کو برادر کر رہے ہیں۔ جب دہلی میں ہماری حکومت سچی تو ہم نے اساتذہ کو عزت دی، ان پر سے غیر بے نقاب کرتا ہے۔ بی جے پی کے لیے تعلیم کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ اساتذہ کی توجہ کر رہے ہیں اور اسکولوں کو برادر کر رہے ہیں۔ جب دہلی میں ہماری حکومت سچی تو ہم نے اساتذہ کو عزت دی، ان پر سے غیر

ضروری بوجھ ہٹایا اور بچوں کی تعلیم کو ہی سب سے بڑی ترجیح بنایا۔ اساتذہ کو تربیت کے لیے بیرون ملک بھیجا، اسکولوں کو بہتر بنایا۔ اساتذہ یہ یقینی بنائیں گے کہ کتوں کی نس بندی ہو اور وہ اسکول کیمپس کے اندر داخل نہ ہوں۔ لیکن جب دہلی میں عام آدمی پارٹی کی حکومت تھی تو صورتحال بالکل مختلف تھی۔ اگر اسکول کی عمارت خراب ہوتی تھی، بیچ بدلے ہوتے تھے یا صفائی کروانی ہوتی تھی تو ان کاموں کے لیے اسٹیٹ مینیجر مقرر ہوتے تھے۔ اساتذہ کو غیر ضروری کاموں سے الگ رکھا گیا تھا۔

آج بی جے پی حکومت سب کچھ برادر کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ ادھر عام آدمی پارٹی کے دہلی ریاستی کنوینر سوربھ بھارادواج نے بھی ایکس پر بی جے پی کی دہلی حکومت کے حکمہ تعلیم کی جانب سے جاری حکم نامے کی کاپی

نئی دہلی (پریس ریلیز) عام آدمی پارٹی نے 5 جنوری سے شروع ہونے والے دہلی اسمبلی کے سرمائی اجلاس کے دوران بی جے پی حکومت کے 10 ماہ کے اقتدار کی ناکامیوں کو اسمبلی میں سختی سے اٹھانے کی تیاری کر لی ہے۔ آپ کے رکن اسمبلی اور چیف وپ سنجیو جھانے کہا کہ عام آدمی پارٹی سرمائی اجلاس میں بی جے پی حکومت کے 10 ماہ کے کام کا پورا حساب لے گی۔ بی جے پی حکومت نے خواتین کو 2500 روپے نہ دے کر اپنے ہی وزیر اعظم کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے۔ ان دس مہینوں میں بی جے پی حکومت بڑی بڑی باتیں کرنے کے علاوہ نہ تو دہلی کی ہوا صاف کر پائی اور نہ ہی دریائے یمنہ کے آلودگی میں کوئی کمی لاسکی۔ چھٹھ پوجا کے موقع پر بی جے پی نے سب کو یمنہ میں ڈبی گلوانی اور آچن کروایا، لیکن

بھارت نے مالی سال 25 میں 5.5 لاکھ ٹریڈ مارک رجسٹر کیے: پیش گوئی



دینے کی مخلصانہ کوششوں نے عالمی انٹلیجنس پرائیمنٹ منظر نامے میں ملک کی پوزیشن کو مضبوط کیا ہے، جس سے اختراع کی قیادت میں ترقی کو فروغ ملتا ہے جس سے نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کو فائدہ ہوتا ہے۔ گوگل نے مزید کہا کہ رجسٹرڈ ٹریڈ مارکس کی سب سے زیادہ تعداد فارما سیویٹیکل، ویٹری اور بیٹری تیاریوں میں تھی۔ پالیسی میں اصلاحات،

نئی دہلی (ایجنسیاں) تجارت اور صنعت کے وزیر پیش گوئی نے منگل کے روز کہا کہ 2024-25 کے دوران ہندوستان میں ٹریڈ مارکس کے لئے 5.5 لاکھ سے زیادہ گھریلو فائلنگ کی ریکارڈ تعداد میں کی گئی، جو اختراع کرنے والوں اور تخلیق کاروں کے مفادات کے تحفظ میں ملک کے اداروں کی مضبوطی کو ظاہر کرتی ہے جو اقتصادی ترقی کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم مودی کے انیڈیٹ ان انڈیا، انویسٹ ان انڈیا، میک ان انڈیا اور میک فارڈی ورلڈ کے منتر کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ ٹریڈ مارکس ایکٹ، 1999، پچھلے 26 سالوں سے اختراع کاروں کے مفادات کے تحفظ میں ایک اہم ستون رہا ہے۔ "اس کے ساتھ ساتھ، وزیر مودی حکومت کی اختراعی ماحولیاتی نظام کو فروغ

دہلی کا تعلیمی ماڈل 10 سال کی مسلسل محنت کا نتیجہ ہے

ہم اسے بی جے پی حکومت کو بر باد نہیں کرنے دیں گے: کل دیپ کمار



کی تعلیم پر توجہ دے سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف اروند کچر یووال کی حکومت تھی، جس نے سرکاری اسکولوں کے اساتذہ کو ملک و بیرون ملک مختلف مقامات پر تربیت کے لیے بھیجا تا کہ بچوں کو جدید اور عالمی معیار کی تعلیم ملے، اور دوسری طرف بی جے پی کی موجودہ حکومت ہے جو انہی اساتذہ کو اسٹریٹ ڈاگز کی گنتی اور نگرانی میں لگا رہی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک آئی آئی ٹی پاس وزیر اعلیٰ کی گورنس کیا تھی اور موجودہ حکومت کی گورنس کیسی ہے۔ سنجیو جھانے دہلی حکومت کے محکمہ تعلیم کی جانب سے جاری حکم نامہ دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ نوٹیفکیشن 20 نومبر کو جاری ہوا تھا۔ یہ سرکلر

سنجیو جھانے کہا کہ دہلی کی بی جے پی حکومت نے ایک عجیب و غریب حکم جاری کیا ہے، جس کے مطابق دہلی کے سرکاری اسکولوں میں پڑھانے والے اساتذہ کو اب اسٹریٹ ڈاگز کی نگرانی کے کام میں لگا دیا جائے گا۔ جب دہلی کے عوام نے اس حکم پر تنقید شروع کی تو وزیر تعلیم آیشیش سود نے غمت میں ایک ویڈیو جاری کر کے دعویٰ کیا کہ ایسا کوئی حکم جاری نہیں ہوا اور جھوٹی خبریں پھیلانی جارہی ہیں۔ وزیر تعلیم کا یہ رویہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کس طرح محکمہ تعلیم اور پوری انتظامیہ کو چلا رہے ہیں۔ یا تو وہ محکمہ کے کام کاج سے بالکل ناواقف ہیں اور محکمہ کوئی اور چلا رہا ہے، یا پھر وہ جان بوجھ کر جھوٹ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سنجیو جھانے کہا کہ 2015 سے پہلے بھی دہلی کے سرکاری اسکولوں میں اس طرح کے احکامات آتے تھے اور اساتذہ کو پڑھانے کے بجائے دیگر کاموں میں لگایا جاتا تھا۔ لیکن جب دہلی میں عام آدمی پارٹی کی حکومت بنی اور منیش سسودیا پہلی بار وزیر تعلیم بنے تو انہوں نے تمام اسکولوں اور محکموں کو ترقی پر حکم دیا کہ دہلی کے سرکاری اساتذہ صرف بچوں کو پڑھائیں گے اور کوئی دوسرا کام نہیں کریں گے۔ صفائی، عمارتوں، ڈبیک اور بیچوں کی دیکھ بھال سمیت دیگر کاموں کے لیے اسٹیٹ مینیجر مقرر کیے گئے تا کہ پرنسپل اور اساتذہ کسی اور کام میں نہ انجھیں اور مکمل طور پر بچوں

نئی دہلی (پریس ریلیز) عام آدمی پارٹی نے دہلی کے سرکاری اسکولوں کے اساتذہ سے آوارہ کتوں کی گنتی اور نگرانی کرانے سے متعلق حکم نامہ دکھا کر وزیر تعلیم آیشیش سود کے چیکنج کی قلعی کھول دی ہے۔ منگل کے روز آپ کے سینئر لیڈر اور رکن اسمبلی سنجیو جھانے بی جے پی حکومت کے محکمہ تعلیم کی جانب سے جاری کردہ حکم نامہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ آیشیش سود نے ایسا کوئی حکم دکھانے کا چیلنج دیا تھا، جبکہ دہلی کے ڈائریکٹر آف ایجوکیشن، نارنجہ ویسٹ۔ اسے نے باقاعدہ فہرست جاری کی ہے۔ اس فہرست کے تحت اساتذہ اور اسکول اسٹاف کے نام مانگے گئے ہیں، جنہیں آوارہ کتوں کی گنتی جیسے کاموں میں لگایا جا رہا ہے۔ سنجیو جھانے کہا کہ اروند کچر یووال کی حکومت میں اساتذہ کو بیرون ملک تربیت کے لیے بھیجا جاتا تھا، جبکہ بی جے پی حکومت میں انہی اساتذہ کو آوارہ کتوں کی گنتی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ وزیر تعلیم آیشیش سود کو مشورہ ہے کہ اب یہ نہ نہیں کہ یہ فیصلہ افسران نے خود لے لیا اور حکومت کو اس کی کوئی جانکاری نہیں تھی۔ کیا ان کا محکمہ کوئی اور چلا رہا ہے؟ تعلیم کو ترجیح دینے والی عام آدمی پارٹی کی حکومت اور محض دکھاوے کے بیانات دینے والی بی جے پی حکومت میں یہی فرق ہے۔ منگل کو آپ کے ہیڈ کوارٹر میں کل دیپ کمار کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے

دہلی میں سرکاری اسکولوں کے اساتذہ بچوں کو پڑھائیں گے یا سڑکوں پر کتوں کی گنتی کریں گے؟: کچر یووال

شیر کر کے سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی حکومت روز بے ٹکے احکامات جاری کرتی ہے۔ اب اساتذہ پر آوارہ کتوں کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے۔ اساتذہ بچوں کو پڑھائیں گے یا آوارہ کتوں کی نگرانی کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے جاری حکم میں صاف طور پر لکھا ہے کہ اساتذہ کی ڈیوٹی اسٹریٹ ڈاگز کی نگرانی بھی ہوگی۔ اساتذہ یہ یقینی بنائیں گے کہ کتوں کی نس بندی ہو اور وہ اسکول کیمپس کے اندر داخل نہ ہوں۔ لیکن جب دہلی میں عام آدمی پارٹی کی حکومت تھی تو صورتحال بالکل مختلف تھی۔ اگر اسکول کی عمارت خراب ہوتی تھی، بیچ بدلے ہوتے تھے یا صفائی کروانی ہوتی تھی تو ان کاموں کے لیے اسٹیٹ مینیجر مقرر ہوتے تھے۔ اساتذہ کو غیر ضروری کاموں سے الگ رکھا گیا تھا۔ لیکن بی جے پی حکومت اساتذہ پر کتوں کی نگرانی جیسی ذمہ داریاں ڈال کر ان کی توجہ کر رہی ہے۔



آج بی جے پی حکومت سب کچھ برادر کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ ادھر عام آدمی پارٹی کے دہلی ریاستی کنوینر سوربھ بھارادواج نے بھی ایکس پر بی جے پی کی دہلی حکومت کے حکمہ تعلیم کی جانب سے جاری حکم نامے کی کاپی

سرمائی اجلاس میں بی جے پی حکومت کے 10 ماہ کے کام کا حساب لے گی آپ: سنجیو جھا



اب وزیر ماحولیات منجندر سنگھ کہہ رہے ہیں کہ یمنہ کا پانی نہانے کے قابل نہیں ہے۔ سنجیو جھانے کہا کہ دہلی میں بی جے پی کی حکومت کو بے 10 مہینے ہو چکے ہیں۔ اب بی جے پی حکومت کو بتانا چاہیے کہ اس نے ان 10 مہینوں میں دہلی کے عوام کے مفاد میں کیا کام کیا ہے؟ بی جے پی نے اپنے انتخابی منشور میں جھوٹے وعدے کر کے دہلی کی عوام سے ووٹ لے لیے اور حکومت بنا

سماجی تحفظ کی فراہمی میں

بھارت دنیا میں دوسرے نمبر پر نئی دہلی (ایجنسیاں) نئی عالمی رپورٹ کے مطابق بھارت اپنے شہریوں کو سماجی تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے دنیا میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکومتی اسکیموں، ڈیجیٹل نظام اور فلاحی پروگراموں کے موثر نفاذ کے باعث کروڑوں افراد کو سماجی تحفظ کی سہولتیں میسر آئی ہیں۔ ماہرین کے مطابق صحت، پنشن، بیمہ اور مالی معاونت سے متعلق منصوبوں کی توسیع نے کم آمدنی والے طبقات کو خاص طور پر فائدہ پہنچایا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ سماجی تحفظ کے دائرہ کار کو مزید بڑھانے اور مستحقین تک بروقت سہولتیں پہنچانے کے لیے اصلاحات مکمل جاری رکھا جائے گا۔

سرمائی اجلاس میں بی جے پی حکومت کے 10 ماہ کے کام کا حساب لے گی آپ: سنجیو جھا

بی جے پی نے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس کی حکومت بنی تو دہلی کی خواتین کو 2500 روپے ماہانہ دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے خود ایک انتخابی جلسے میں دہلی کی خواتین سے یہ وعدہ کیا تھا، لیکن بی جے پی حکومت نے تو اپنے وزیر اعظم کو بھی جھوٹا ثابت کر دیا۔ سنجیو جھانے دریائے یمنہ کی صفائی کے معاملے پر بھی بی جے پی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ یمنہ کو صاف کر دے گی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ پیر کے روز وزیر ماحولیات منجندر سنگھ سراسیمہ کہہ رہے تھے کہ یمنہ میں ڈبی نہیں لگائی جا سکتی، جبکہ ڈیڑھ مہینہ پہلے چھٹھ پوجا کے دوران بی جے پی کے ہی رہنماؤں نے سب کو یمنہ میں ڈبی لگوائی تھی اور آچن بھی کروایا تھا۔

دہلی کا تعلیمی ماڈل 10 سال کی مسلسل محنت کا نتیجہ ہے

ہم اسے بی جے پی حکومت کو بر باد نہیں کرنے دیں گے: کل دیپ کمار

جھانے کہا کہ اگر محکمہ تعلیم اسی طرح چلا یا گیا تو دس سال میں حاصل کیے گئے سنگ میل کی توجہ نہ ہوگی۔ یہ ان اساتذہ کی بھی توجہ ہے جو گزشتہ دس سال سے غریب بچوں کے مستقبل کو سنوار رہے ہیں اور سرکاری اسکولوں کے نتائج بہتر بنا رہے ہیں۔ اساتذہ کو اس طرح کے کاموں میں لگانا ان کی بے عزتی ہے، جس کی دہلی ٹیچرز یونین نے بھی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے بچے اور ان کے والدین اس بات سے مطمئن تھے کہ اب سرکاری اسکولوں کی تعلیم بہتر ہوگئی ہے اور بچوں کے مستقبل سے کھلاؤ نہیں ہوگا، لیکن یہ نیا حکم اور وزیر تعلیم کی ویڈیو ظاہر کرتی ہے کہ اب سرکاری اسکولوں کی حالت مزید خراب کی جا رہی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ وزیر تعلیم آیشیش سود اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں گے، خود احتسابی کریں گے اور ایسے بے ٹکے احکامات جاری نہیں کریں گے تا کہ دہلی کے سرکاری اسکولوں کے اساتذہ کو کوئی عزت ملتی رہے جو عام آدمی پارٹی کی حکومت کے دوران ملتی رہی۔ اس موقع پر کوئٹہ سے آپ کے رکن اسمبلی کل دیپ کمار نے کہا کہ گزشتہ دس سالوں میں اروند کچر یووال کی حکومت کے دوران دہلی کے سرکاری اسکولوں نے عالمی سطح پر ایک شناخت اور مقام حاصل کیا تھا۔ منیش سسودیا ایسے وزیر تعلیم تھے جو پورا وقت اسکولوں میں گزارتے تھے۔

ڈائریکٹر ایٹ آف ایجوکیشن کی کیئر ٹیکنگ برائج کا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پیر کو آیشیش سود حکم دکھانے کا چیلنج دے رہے تھے، جبکہ یہ حکم ان کے ہی محکمہ کا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یا تو وزیر تعلیم اپنے ہی محکمہ سے بالکل ناواقف ہیں، یا محکمہ کوئی اور چلا رہا ہے، یا وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ صرف نوٹیفکیشن ہی نہیں بلکہ ضلع نارنجہ ویسٹ کے ڈی ڈی ای کی جانب سے جاری مکمل فہرست بھی موجود ہے، جس میں واضح طور پر درج ہے کہ کن اساتذہ کو آوارہ کتوں سے متعلق معاملات کے لیے نوڈل افسر بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اروند کچر یووال کی حکومت میں منیش سسودیا نے تعلیم کے میدان میں ایسا کام کیا جس کی نہ صرف دہلی بلکہ ملک و بیرون ملک تعریف ہوئی۔ کچر یووال ماڈل آف گورنس میں تعلیم ایک اہم ستون تھا۔ دس سال پہلے لوگ پرائیویٹ اسکولوں میں داخلے کے لیے سفارشیں کرواتے تھے، لیکن آپ کی حکومت میں سرکاری اسکول اتنے شاندار ہو گئے کہ پرائیویٹ اسکولوں کے طلبہ میں بھی سرکاری اسکولوں میں داخلے کی دوڑ لگ گئی۔ سنجیو جھانے وزیر تعلیم آیشیش سود کو نصیحت کی کہ جس عظیم وراثت کو وہ سنبھال رہے ہیں، اسے سنبھالنا آسان نہیں، لیکن کم از کم جھوٹ نہ بولیں اور محکمہ کی مکمل جانکاری رکھیں۔ بغیر تیاری کے ویڈیو جاری کرنے سے پہلے حقائق کی جانچ کر لیں۔ سنجیو